लखनऊ

मंगलवार, 11 अगस्त , 2026

वर्ष : 11 । अंक: 342

मूल्य : 1 रुपये

पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

महानता कभी न गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है।

TODAY WEATHER

DAY 32° Hi

NIGHT 28° Low

संक्षेप

वीबी-जी रैम जी को कांग्रेस ने बताया जॉब स्कैम, मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस ने सोमवार को मोदी सरकार पर वीबी-जी रैम जी एक्ट को लागू करने को लेकर रोज़गार चोरी का आरोप लगाया। पार्टी का दावा है कि सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि जुलाई में ग्रामीण रोज़गार पैदा होने में भारी गिरावट आई है; यह नया कानून मनरेगा की जगह लागू होने के बाद पहला महीना था। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने X पर एक मीडिया रिपोर्ट शेयर की, जिसमें सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया कि जुलाई में नए ग्रामीण रोज़गार गारंटी प्रोग्राम के तहत पैदा हुए रोज़गार के 'पर्सन-डेज़' (काम के दिनों) में साल-दर-साल 49.94% की गिरावट आई है। रमेश ने कहा कि मोदी सरकार के वीबी-जी रैम जी का पहला महीना ही मनरेगा को खत्म करने की कीमत दिखा रहा है। उनके बताए आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2025 की तुलना में रोज़गार पाने वाले परिवारों की संख्या में 51.45% की गिरावट आई है, जब मनरेगा लागू था। रोज़गार के 'पर्सन-डेज़' (काम के दिनों) में भी लगभग 50% की कमी आई। रमेश ने कहा कि ये आंकड़े उन चेतावनियों के अनुरूप हैं जो कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने मनरेगा को हटाए जाने के समय दी थीं। उन्होंने कहा कि ठीक यही बात कांग्रेस और पूरे विपक्ष ने तब कही थी जब मोदी सरकार ने मनरेगा को ज़बरदस्ती खत्म कर दिया था। रमेश ने कहा कि MGNREGA ने ग्रामीण मज़दूरों को रोज़गार की कानूनी गारंटी दी थी और ग्राम पंचायतों को इस योजना को लागू करने के लिए सशक्त बनाया था।

आरजी कर रेप-मर्डर केस: CBI का एक्शन, सबसे पहले शव मिलने की सूचना देने वाली महिला का फोन जब्त

कोलकाता, एजेंसी। अगस्त 2024 में कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की एक जूनियर डॉक्टर से रेप और मर्डर की नए सिरे से जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की नई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) ने हॉस्पिटल की एक महिला कर्मचारी का मोबाइल जब्त कर लिया है। 9 अगस्त 2024 की सुबह जब सेमिनार रूम में महिला जूनियर डॉक्टर का शव मिला, तो आरजी कर की महिला कर्मचारी ने सबसे पहले पीड़ित के परिवार को घटना की जानकारी दी थी। सूत्रों ने बताया कि परिवार को घटना की जानकारी देने वाली महिला कर्मचारी का मोबाइल जब्त कर लिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया, क्योंकि पीड़ित के परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि घटना की जानकारी देने के लिए कुछ ही समय के भीतर किए गए कई कॉल्स में उस महिला कर्मचारी ने अलग-अलग और विरोधाभासी बातें बताई थीं। जब्त किए गए मोबाइल को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। सूत्रों ने आगे बताया कि जांचकर्ता घटना से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब खोजने के लिए फोन कॉल रिकॉर्ड और दूसरी जानकारियों की जांच कर रहे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी की नई एसआईटी के सदस्य इस बात की जांच कर रहे हैं कि अस्पताल की महिला कर्मचारी ने किसके कहने पर और कैसे पीड़िता के परिवार से संपर्क किया। जांच अधिकारी पीड़िता के परिवार के उन आरोपों की भी पुष्टि करने की कोशिश कर रहे हैं।

संसद में गतिरोध पर खरगे का पीएम मोदी-शाह पर हमला, बोले- बयान दें या इस्तीफा दें

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार को संसद के दोनों सदनों में जारी गतिरोध को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार संसद को चलाने के लिए जरूरी चर्चा से बच रही है और विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे रही है। खरगे ने कहा कि विपक्ष बहस चाहता है और उसकी मांग सिर्फ इतनी है कि गृह मंत्री अमित शाह छात्रों के साथ कथित अन्याय और ज्यादती के मुद्दे पर सदन में बयान दें। खरगे ने कहा कि विपक्ष पिछले 17 दिनों से अमित शाह से सदन में आकर छात्रों के साथ हुए कथित अन्याय और ज्यादती पर बयान देने की मांग कर रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार दूसरे मुद्दों पर बयान देती है, लेकिन इस मामले पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहती। खरगे के मुताबिक, विपक्ष केवल बयान और चर्चा की मांग कर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि दोनों सदनों के कामकाज में बाधा के लिए सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। खरगे ने कहा कि विपक्ष बहस चाहता है, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर जवाब नहीं दे रही। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों और युवाओं की समस्याओं का समाधान नहीं करना चाहती। खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर संसद की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सदन में जवाब देने के बजाय प्रधानमंत्री रात में इंस्टाग्राम पर रील बना रहे हैं। उन्होंने इसे सांसदों और जनता का अपमान बताया और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन को सुचारू रूप से चलाना नहीं चाहते।

संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने किया विरोध प्रदर्शन, अमित शाह से सदन में जवाब देने की मांग

नई दिल्ली, एजेंसी। संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष और सरकार के बीच गतिरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। विपक्षी सांसदों ने दिल्ली में 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संसद में बयान देने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि जब तक गृह मंत्री इन मुद्दों पर सदन में स्पष्टीकरण नहीं देते, तब तक विपक्ष कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा आगे नहीं बढ़ने देगा। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि गतिरोध तब तक बना रहेगा, जब तक केंद्रीय गृह मंत्री संसद में बयान नहीं देते।

कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने भी विपक्ष की मांग को स्पष्ट करते हुए कहा कि किसी भी विधेयक, जिसमें एफसीआरए बिल भी शामिल है, पर चर्चा से पहले अमित शाह को संसद में आकर दिल्ली के छात्रों के खिलाफ हुई कार्रवाई पर बयान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह विपक्ष की स्पष्ट मांग है और बयान के बिना सरकार को इन मामलों पर आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। एफसीआरए बिल को लेकर भी विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि पार्टी इस विधेयक को एक बड़े समुदाय के खिलाफ उठाए गए कदम के रूप में देखती है। उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित बदलाव समुदाय और देश के हितों के खिलाफ हैं तथा इससे शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण संसाधनों पर असर पड़ सकता है।

एक राज्य का बदलेगा नाम, संसद में पेश होंगे कई अहम बिल, विपक्ष की मांग पर फिर हो सकता है हंगामा

नई दिल्ली, एजेंसी। संसद के मानसून सत्र में सोमवार को एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव के आसार हैं। विपक्ष छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संसद में जवाब की मांग कर रहा है। वहीं, केंद्र सरकार लोकसभा और राज्यसभा में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की तैयारी में है। कांग्रेस ने प्रस्तावित विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक का भी संसद में जोरदार विरोध करने का ऐलान किया है।

छात्रों पर कार्रवाई को लेकर कांग्रेस हमलावर

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि घटना को 13 दिन बीत जाने के बावजूद गृह मंत्री की ओर से इस मामले पर कोई जवाब नहीं आया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर जवाबदेही तय करने की मांग की।

कांग्रेस का कहना है कि सरकार को संसद में स्पष्ट करना चाहिए कि छात्रों के खिलाफ लाठीचार्ज, पैलेट गन और आंसू गैस के इस्तेमाल का आदेश किस स्तर से दिया गया।

सरकार की ओर से कई विधेयक पेश करने की तैयारी

विपक्ष के विरोध के बीच केंद्र सरकार सोमवार को संसद में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की तैयारी में है। लोकसभा की कार्यसूची में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संबंधित केरल नाम परिवर्तन विधेयक और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक शामिल हैं। वहीं, राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी एक विधेयक पेश करेंगी।

स्नष्टक्रर संशोधन विधेयक पर विपक्ष का विरोध

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने केरल के अलाप्पुझा में कहा कि यदि केंद्र सरकार स्नष्टक्रर संशोधन विधेयक संसद में पेश करती है तो कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इसका विरोध करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रस्तावित कानून अल्पसंख्यकों और गैर-सरकारी संगठनों को प्रभावित करने वाला है। वेणुगोपाल ने प्रस्तावित परिसीमन विधेयक पर भी आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे उन राज्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को सफलतापूर्वक लागू किया है।

हर आंसू की बूंद से लग रहा था जैसे गोल्ड मेडल टपक रहा है, मीराबाई चानू से बोले पीएम मोदी

नई दिल्ली, एजेंसी। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में देश के लिए मेडल लेकर लौटे भारतीय खिलाड़ियों से रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर खास मुलाकात की। पीएम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार तीसरी बार गोल्ड मेडल जीतने वालीं मीराबाई चानू के प्रदर्शन की तारीफ की।

दरअसल, मीराबाई चानू गोल्ड मेडल जीतने के बाद भावुक हो गई थीं और पोडियम पर मेडल लेते वक्त अपने आंसू पर काबू नहीं रख सकी थीं। पीएम मोदी ने मीराबाई से उनके रोने का कारण पूछते हुए कहा, इतने आंसू टपक रहे थे कि मुझे लगता है कि हर आंसू के बूंद से गोल्ड मेडल टपक रहा हो। मीराबाई ने प्रधानमंत्री को जवाब देते हुए कहा, मैं उस दिन बहुत खुश और भावुक थी। मैं गोल्ड मेडल जीतने के बाद उस दिन इसलिए रोई थी, क्योंकि पेरिस ओलंपिक में मेरा मेडल सिर्फ एक किलो से रह गया था।

भारतीय महिला वेटलिफ्टर ने आगे कहा, एक खिलाड़ी के तौर पर आपको बहुत चीजों का सामना करना पड़ता है। इन चार वर्षों के अंदर मैंने काफी चीजों का सामना किया था। हर समय इंजरी ही चल रही थी और परिवार में भी समस्याएं हो रही थीं। मैंने इन 4 वर्षों में बहुत चीजों का सामना किया था। इसी कारण जब मैं पोडियम पर खड़ी थी और जब हमारा नेशनल एंथम बजा, तो मैं खुद को रोक नहीं सकी। देश का झंडा ऊपर देखकर हमारे अपने आप ही आंसू निकल आते हैं।

मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स में निरंतरता के साथ लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने यह लगातार तीसरे कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। मीराबाई यह उपलब्धि हासिल करने वाली दुनिया की पहली वेटलिफ्टर बनीं।

अच्छे केस को खराब मत करो वकील अश्विनी उपाध्याय को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दी ये सलाह

नई दिल्ली, एजेंसी। 14 साल तक के बच्चों को सेक्युलर/धार्मिक शिक्षा देने वाले सभी संस्थानों के रजिस्ट्रेशन, मान्यता, सुपरविज़न और मॉनिटरिंग की मांग के से जुड़े मामले में लेकर सोमवार (10 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट ने वकील अश्विनी उपाध्याय को एक अहम सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपने ही अच्छे केस को खराब मत करो। कोर्ट ने कहा कि रिट नहीं अवमानना याचिका दायर करें। जिसके बाद वकील ने याचिका वापस ले ली। इस मामले पर जस्टिस अरविंद कुमार ने वकील अश्विनी उपाध्याय से कहा कि आप पहले भी इस कोर्ट में आए थे। कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए 'रिट ऑफ़ मैंडमस' जारी किया था कि वो दो महीने के भीतर आपकी अर्ज़ी पर विचार करें।

राम मंदिर चंदा चोरी पर संसद में हंगामा, अखिलेश ने भाजपा पर बोला हमला

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (SP) के सांसद अखिलेश यादव ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी ज़मीन माफ़िया पार्टी बताते हुए संसद में जारी गतिरोध को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और अयोध्या के राम मंदिर के लिए मिले चंदे में कथित हेराफेरी पर जवाब मांगा। कानून बनाने को लेकर बने गतिरोध पर पत्रकारों से बात करते हुए, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से 'फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट' संशोधन बिल के बारे में सवाल किया।

अखिलेश यादव ने कहा कि हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि लाठीचार्ज क्यों किया गया, आंसू गैस के गोले क्यों छोड़े गए और इलेक्ट्रिक शॉक क्यों दिए गए? अब वे FCRA ला रहे हैं। जबकि भारत सरकार और BJP ने हमें भरोसा दिलाया था कि भारत का पैसा देश से बाहर नहीं जाएगा। अनगिनत लोगों ने आधिकारिक और अनौपचारिक, दोनों तरीकों से भारत से भारी मात्रा में पैसा बाहर भेजा है... सच तो यह है कि वे संस्थानों पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। वे FCRA के ज़रिए इन संस्थानों पर नियंत्रण करने के तरीके ढूंढ रहे हैं।

रांची में जेपीएससी-जेएसएससी छात्रों का विधानसभा मार्च, वाटर कैनन के सामने किया डांस, तोड़े बैरिकेड!

नई दिल्ली, एजेंसी। सोमवार को रांची में हज़ारों नाराज़ छात्रों ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़ दिए और राज्य की पब्लिक सर्विस भर्ती प्रक्रिया में फैले भ्रष्टाचार के विरोध में झारखंड विधानसभा की ओर मार्च किया। यह विशाल विधानसभा घेराव लगातार 17वें दिन जारी भारी विरोध-प्रदर्शन का हिस्सा है; यह विरोध झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (JPSC) और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षाओं में पेपर लीक, रिश्वतखोरी और धांधली के बड़े पैमाने पर लगे आरोपों के कारण शुरू हुआ था।

छात्र प्रदर्नकारियों के सातवें और आखिरी बैरिकेडिंग तक पहुंचते ही पुलिस ने उनपर वाटर कैनन एक्शन शुरू कर दिया. ऐसे में छात्र पानी में जमकर डांस करने लगे और कहने लगे- और चलाओ, और चलाओ। 'विधानसभा घेराव' मार्च के दौरान छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि जब सरकार ने नुकीले बैरिकेड लगाए, तो तबीयत ठीक न होने के बावजूद मैं खुद को रोक नहीं पाया। क्या यह पाकिस्तान, बांग्लादेश या चीन का बॉर्डर है? ये छात्र हैं। खबरों के मुताबिक, झारखंड विधानसभा की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़ दिए। प्रदर्शनकारियों को पहले 'ओल्ड विधानसभा चौक' के पास रोका गया था, लेकिन वे बैरिकेड्स पार करके आगे बढ़ गए। रास्ते में पुलिस और सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं, और प्रदर्शन वाली जगह के पास वॉटर कैनन और दंगा-रोधी गाड़ियां भी मौजूद हैं। मार्च का नेतृत्व कर रहे वॉलंटियर्स प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। अखबार सुरक्षा के कड़े इंतज़ामों के बीच प्रदर्शनकारी झारखंड विधानसभा परिसर के और करीब पहुँच गए हैं। विधानसभा का मॉनसून सत्र अभी चल रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच प्रदर्शनकारी झारखंड विधानसभा के करीब पहुँच रहे हैं। उन्होंने पुलिस की कई बैरिकेडिंग तोड़ी और उन्हें रोकने के लिए वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन ये उपाय उन्हें राज्य विधानसभा के और करीब जाने से नहीं रोक पाए। रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को झारखंड विधानसभा की ओर मार्च करने से रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने वॉटर कैनन तैनात किए हैं।

रिपोर्ट में खुलासा

प्राइवेट सेक्टर में महज 18% महिला रिसर्चर

सरकारी कंपनियों से भी पीछे

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत के निजी क्षेत्र के अनुसंधान और विकास में महिला शोधकर्ताओं की भागीदारी केवल 17.8 प्रतिशत है। यह सार्वजनिक संस्थानों में महिलाओं के 21.2% प्रतिनिधित्व से काफी पीछे है, यह स्थिति तब है जब अनुसंधान पर खर्च के मामले में उद्योग जगत लगभग सरकार की बराबरी कर रहा है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2025-26 की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। यद्यपि निजी क्षेत्र में यह संख्या कम है, फिर भी अनुसंधान कार्यबल में महिलाओं की समग्र भागीदारी में वृद्धि के कारण यह आंकड़े एक दिलचस्प तस्वीर पेश करते हैं।

एक अप्रैल 2024 तक, भारत में 5 लाख से कुछ अधिक पूर्णकालिक शोधकर्ता थे, जिनमें लगभग 1.5 लाख महिलाएं थीं। शोध क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी 2020-21 के 18.6 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 29 प्रतिशत हो गई है।

उच्च शिक्षा का दबदबा

क्षेत्रवार आंकड़ों का विश्लेषण करने पर निजी उद्योग सबसे निचले पायदान पर नजर आता है। महिलाओं की हिस्सेदारी के मामले में उच्च शिक्षा क्षेत्र 36 प्रतिशत के साथ सबसे आगे है। इसके बाद राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और अन्य अनुसंधान प्रयोगशालाओं में 28 प्रतिशत, सरकार द्वारा वित्तपोषित अनुसंधान में 21.9 प्रतिशत, सार्वजनिक क्षेत्र में 21.2 प्रतिशत और सबसे अंत में निजी क्षेत्र का स्थान आता है।

नेतृत्व की भूमिका में महिलाओं के बढ़ते कदम

रिपोर्ट के अनुसार, अनुसंधान नेतृत्व में महिलाओं की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हुआ है। केंद्र द्वारा वित्तपोषित एक्स्ट्राम्यूरल परियोजनाओं में प्रोजेक्ट हेड के रूप में महिलाओं की भागीदारी 2000-01 में मात्र 13 प्रतिशत थी, जो 2023-24 में बढ़कर 28 प्रतिशत हो गई है। पिछले दो वर्षों के दौरान, लगभग 30 प्रतिशत प्रोजेक्ट लीडर महिलाएं रही हैं, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि उनकी भूमिका अब केवल भागीदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि वे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का नेतृत्व भी कर रही हैं।

रिसर्च फंडिंग में भारत की स्थिति

वर्ष 2023-24 में सरकार द्वारा समर्थित एक्स्ट्राम्यूरल रिसर्च फंडिंग 6,094 परियोजनाओं के लिए 3356 करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जिसमें से लगभग तीन-चौथाई हिस्सा शैक्षणिक संस्थानों को प्राप्त हुआ। इस फंडिंग में आधे से अधिक का योगदान अकेले विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने दिया है। वर्तमान में, अनुसंधान और विकास पर खर्च होने वाले प्रत्येक 100 रुपये में सरकार का योगदान लगभग 48 रुपये है, जबकि निजी उद्योग लगभग 45 रुपये का योगदान दे रहा है।

अमरनाथ यात्रा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, जम्मू-कश्मीर में अगले दो दिनों में भारी बारिश का पूर्वानुमान

श्रीनगर। उत्तर और दक्षिण कश्मीर के बालटाल एवं पहलगाम मार्गों पर ट्रैक क्षतिग्रस्त होने तथा खराब मौसम को लेकर जारी चेतावनी के कारण अमरनाथ यात्रा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि दोनों बेस कैंप से जाने वाले दो रास्तों को ठीक करने में काफी समय लगेगा। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्री अमरनाथ जी यात्रा-2026 को रोक दिया गया है और बेस कैंप तथा जम्मू में भगवती नगर यात्री निवास में मौजूद सभी तीर्थयात्रियों से घर लौटने को कहा गया है। अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण भी बंद कर दिया गया है और अब श्रद्धालुओं को कश्मीर घाटी की ओर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, छड़ी मुबारक (भगवान शिव की पवित्र गदा) पारंपरिक पहलगाम मार्ग से यात्रा करते हुए 28 अगस्त को पवित्र गुफा तक पहुंचेगी। इसी दिन अमरनाथ यात्रा का औपचारिक समापन होगा। 3 जुलाई से शुरू हुई 57 दिनों की श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के दौरान अब तक 4.80 लाख से अधिक श्रद्धालु समुद्र तल से 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। अधिकारियों ने कहा कि अब केवल उन्हीं यात्री काफिलों को जाने की इजाजत होगी जो तीर्थयात्रियों को घाटी से वापस ला रहे होंगे। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में जम्मू-कश्मीर में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। पवित्र गुफा मंदिर की भौगोलिक स्थिति और ऊंचाई को देखते हुए, खराब मौसम का आने वाले दिनों में यात्रा के दोनों रास्तों और गुफा मंदिर क्षेत्र पर बहुत बुरा असर पड़ेगा।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस: रामानंदी परंपरा का ही हो अधिकारी, CEO की नियुक्ति से पहले संतों की बड़ी मांग

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

अयोध्या। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक तौर पर कई बदलाव किए गए हैं। इधर मंदिर की व्यवस्था के बेहतर संचालन के लिए CEO की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज हो गई है। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने CEO पद के लिए भर्ती निकाली थी। जिसके लिए करीब 5300 लोगों ने आवेदन किया। इनमें अलग-अलग क्षेत्रों के लोग शामिल हैं। इस बीच CEO की नियुक्ति से पहले संत समाज की बड़ी मांग सामने आई है।

संत समाज का कहना है कि मंदिर और आश्रम की परंपराओं की समझ रखने वाला व्यक्ति ही श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का CEO बने। उनका कहना है कि रामानंदी परंपरा से जुड़े व्यक्ति को CEO की

जिम्मेदारी मिले। मंदिर ट्रस्ट की धार्मिक समिति की बैठक में यह मुद्दा उठा। सदस्यों ने मठ-मंदिरों के संचालन करने वालों को ही राम मंदिर की जिम्मेदारी दिए जाने की बात कही।

आचार्य मिथिलेशनन्दिनीशरण की राय

ट्रस्ट की धार्मिक समिति के सदस्य एवं सिद्धपीठ हनुमन्निवास के महंत आचार्य मिथिलेशनन्दिनीशरण ने CEO की नियुक्ति को लेकर अपनी राय रखी। आचार्य ने कहा कि मंदिरों को मूल रूप से CEO के माध्यम से नहीं चलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंदिर की व्यवस्था और अधिकार भगवान के प्रति निष्ठावान लोगों के पास ही होने चाहिए।

CEO पद के लिए किसे मिले प्राथमिकता

मीडिया से बातचीत के दौरान आचार्य मिथिलेशनन्दिनीशरण ने कहा कि CEO पद के लिए ऐसे व्यक्ति को प्राथमिकता मिले, जिसका जीवन मठ-मंदिर और आश्रम की परंपराओं में बीता हो। उन्होंने कहा कि धार्मिक परंपराओं, पूजा-पद्धति और मंदिर व्यवस्था की गहरी जानकारी रखने वाले व्यक्ति को ही यह जिम्मेदारी सौंपी जाए।

प्रशासनिक के साथ धार्मिक समझ जरूरी

ट्रस्ट के CEO को लेकर संत समाज ने प्रशासनिक दक्षता के साथ धार्मिक समझ को भी जरूरी बताया। उन्होंने मंदिर प्रबंधन में परंपरा और आस्था को प्राथमिकता देने की मांग की। उनका कहना है कि केवल प्रशासनिक अनुभव को आधार न बनाया जाए। उनका कहना है कि प्रशासनिक दक्षता रखने वाला व्यक्ति मंदिर की व्यवस्था तो संभाल सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति की निष्ठा भगवान के बजाय प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति ज्यादा होने की आशंका हो सकती है।

CEO की नियुक्ति को लेकर संतों की मांग से राम मंदिर के प्रशासनिक ढांचे और धार्मिक परंपरा के बीच संतुलन का मुद्दा फिर सामने आया। 22 जुलाई की बैठक में आचार्य मिथिलेशनन्दिनीशरण को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा गठित धार्मिक समिति का सदस्य बनाया गया था। उनका कहना है कि देश के कई बड़े मंदिरों में CEO के जरिए से व्यवस्थाएं संचालित हो रही हैं। राम मंदिर में CEO नियुक्त होता है, तो वह इसका विरोध नहीं करेंगे, हालांकि उसकी भूमिका और अधिकार स्पष्ट किया जाना जरूरी होगा।

DGनवगठित धार्मिक समिति की पहली बैठक

अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की नवगठित धार्मिक समिति की पहली बैठक श्री रामवल्लभा कुंज मंदिर में संपन्न हुई। करीब 3 घंटे चली बैठक में ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन, समिति सदस्य मिथिलेश नंदिनी शरण, महंत रामानंद दास, महंत राजकुमार दास समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। समिति के अध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी आनलाइन जुड़े। बैठक में फैसला लिया गया कि 15 अगस्त को शाम करीब 5 बजे राम मंदिर के गर्भगृह से गाजे-बाजे के साथ भगवान राम की पालकी यात्रा निकाली जाएगी।

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से वृद्ध की मौत

सुल्तानपुर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सोमवार को सहंगिया गांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से 70 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई। हादसा एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 165.8 के पास हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दोस्तपुर थाना क्षेत्र के संसारपुर निवासी रामकृपाल (70) पुत्र लौटू निषाद सोमवार को एक्सप्रेसवे पार कर रहे थे। इसी दौरान लखनऊ से गाजीपुर की ओर जा रहे तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में रामकृपाल की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। हादसे की सूचना मिलने पर यूपीडा की टीम और एंबुलेंस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी नारदमुनि सिंह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और आवश्यक कार्रवाई की। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और अन्य माध्यमों से दुर्घटना करने वाले वाहन की पहचान करने में जुटी है।

भाजपा विधायक के आडियो सेंपल की हो जांच : मोनू सिंह

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। पिछले 14 सालों से पूर्व मंत्री और शहर भाजपा विधायक विनोद सिंह मेरे भाई पूर्व विधायक चंद्र भद्र सिंह सोनू और मेरी हत्या का षड्यंत्र रच रहे है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुए ऑडियो ने उनकी कुंठित मानसिकता की पुष्टि कर दी है।उक्त बाते शहर स्थित आवास पास आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व प्रमुख यशभद्र सिंह मोनू ने पत्रकारों से कही। इसके पहले पूर्व प्रमुख ने पुलिस अधीक्षक चारु निगम से मुलाकात कर शिकायती पत्र और वॉयस सैंपल सौंपा तथा उसकी जांच और भाजपा विधायक के ऊपर कार्यवाही की मांग की। पूर्व प्रमुख ने मीडिया कर्मियों से वार्ता करते हुए आगे कहा कि 2014 में हम दो भाइयों की हत्या को लेकर जिला कारागार में बंद पूर्वांचल के माफिया डॉन मुन्ना

बजरंगी से बिना प्रवेश पास के मिलने गए थे जिसमें प्रशासन का छापा पड़ने के बाद काफी देर तक पूर्व मंत्री को बैठाया गया था तब से आज तक हम दोनों भाई शासन प्रशासन से अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहे है पर भाजपा विधायक के प्रभावशाली नेटवर्क के चलते कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि अगर प्रशासन द्वारा वॉयस सैंपल की जांच नहीं कराई जाती है तो वे उच्च न्यायालय का रुख करेंगे।पूर्व प्रमुख मोनू सिंह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए आगे कहा कि इस विषय को लेकर वे सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात कर विधायक के कारनामों की पोल खोलेंगे।

मुमताज हत्याकांड : दरोगा को फोन कर आरोपी बोला– परिवार को परेशान मत करो, 'सब लोग ताकत लगा लो . . . खेल मैं खेलूंगा'

आर्यावर्त संवाददाता

कानपुर। मुमताज हत्याकांड में वारदात के बाद से लापता शोयल खान उर्फ रानू गांव और क्षेत्र की हर घटना पर नजर रखे हुए है। पुलिस शुक्रवार को आरोपी के परिजन को पूछताछ के लिए थाने लेकर आई तो उसने साढ़ कस्बा चौकी में तैनात दरोगा को फोन करते हुए कहा कि मेरे परिवार ने कुछ नहीं किया है। उन्हें क्यों परेशान कर रहे हो।।।।

पिता बीमार हैं, उन्हें छोड़ दो। आरोपी ने कहा कि वह किसी काम से उन्नाव आया हुआ है। जल्द ही घर आ जाएगा। हालांकि, आरोपी की उस दौरान लोकेशन हमीरपुर के पास मिल रही थी। आरोपी ने फिर मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। रविवार दोपहर दो बजे आरोपी ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई। इसमें लिखा था कि जितने मेरे विरोधी हैं वे अब खुलकर

सामने आ चुके हैं और सबने मान लिया है कि इस मामले में मेरा हाथ है।

मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि वह मेरा भी भाई था और मेरा इस केस से कोई लेना-देना नहीं है। केवल शक की बुनियाद पर कार्रवाई न करें। केस की जांच के बाद ही फैसला लें और पुलिस हमारे घरवालों को रिहा करे। स्टोरी का लिंक गांव के कई लड़कों के मोबाइल पर भी भेजा।

सब लोग ताकत लगा लो.. उल्टा खेल मैं खेलूंगा...

आरोपी ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाने के आलावा मुमताज के भतीजे के व्हाट्सएप पर एक ऑडियो भी भेजा। इसमें वह बोलता हुआ सुनाई दे रहा है कि जिस तरीके से मेरे खिलाफ सब लोग ताकत लगा रहे हो।। तो लगा लो। मुझे पता है कि बाहर कैसे निकलना है जब मैंने गलत नहीं किया है। मैं सारे साक्ष्य लेकर भाग जाऊंगा। फिर देखना उल्टा खेल मैं खेलूंगा। ये बता देना उनको। कल्लू(मुमताज) से मेरी कोई लड़ाई नहीं थी। कल को अगर तुम्हारी हत्या हो जाएगी तो क्या मेरा आरोप लगा दोगे। मेरे खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है।

दबंगई से पूरा गांव परेशान है

मुख्य आरोपी शोयल खान उर्फ रानू गांव में अपनी दबंगई के लिए कुख्यात है। उसकी गुंडागर्दी और बदतमीजी से न केवल ग्रामीण बल्कि साढ़ पुलिस भी खासी परेशान रही है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक रानू के खिलाफ पहले से साढ़ थाने में मुकदमा दर्ज है। डर का आलम यह है कि गांव का कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था।

बहन के गहने गिरवी रख शराब पी गया था आशीष

मुमताज की हत्या के दूसरे आरोपी चौकीदार के बेटे आशीष के बारे में पुलिस को पता चला कि वह कुछ दिन पहले अपनी बहन के गहने चुराकर उन्हें गिरवी रख मिले रुपयों से शराब पी गया था। पिता ने जानकारी होने पर पुलिस से शिकायत की थी। वहीं आरोपी की दबंगई के चलते दलेलपुर स्थित शराब ठेका का मैनेजर उसे मुफ्त में शराब पिलाता था। हत्याकांड के पहले भी सभी ने मिलकर शराब पी थी। मुमताज की हत्या के बाद परिवार पर आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया। समाजवादी पार्टी के बिठूर विधानसभा नेता बृजेंद्र यादव ने मुमताज के शव की अंतिम क्रिया के लिए 10 हजार रुपये की सहायता दी।

पौधरोपण के नाम पर लाखों खर्च

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

बल्दीराय/सुल्तानपुर। पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के नाम पर हर वर्ष लाखों रुपये खर्च कर पौधरोपण अभियान चलाया जाता है, लेकिन बल्दीराय क्षेत्र में इसकी जमीनी तस्वीर विभागीय दावों से अलग नजर आती है। सवाल सिर्फ पौधे लगाने का नहीं, बल्कि पौधे लगाने के बाद उन्हें बचाने का है। स्थानीय स्तर पर आरोप है कि रखरखाव और सुरक्षा के अभाव में प्रतिवर्ष लगाए गए करीब 75 प्रतिशत पौधे नष्ट हो जाते हैं। यदि यह स्थिति सही है, तो पौधरोपण पर खर्च होने वाली सरकारी धनराशि के वास्तविक परिणामों की जांच जरूरी हो जाती है।

बल्दीराय क्षेत्र के डोभियारा सहित लगभग 15 स्थानों को वृक्षारोपण के लिए चयनित किया गया है। जिसमे कुछ में पौधरोपण कराया जा रहा है। शीशम, सागौन, अर्जुन और कंजी जैसे पौधे रोपे जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इन पौधों की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? सड़क, नहर और माइनर किनारे लगाए गए पौधों के आसपास कई जगह ट्री गार्ड अथवा ब्रिक गार्ड की पर्याप्त व्यवस्था नहीं दिखाई देती। ऐसे में मवेशियों से चराई, वाहनों की चपेट और अन्य कारणों से पौधों के नष्ट होने का खतरा बना रहता है।

एक महीने के भीतर दो सुसाइड . . . इटावा पुलिस लाइन में महिला सिपाही ने खाया जहर, मौत

आर्यावर्त संवाददाता

इटावा। इटावा पुलिस लाइन में एक महीने के भीतर आत्महत्या की दूसरी घटना सामने आई है। 2 जुलाई को एक सिपाही की पत्नी ने पुलिस लाइन में फांसी लगाकर जान दी थी। वहीं रविवार को सैफई थाने में तैनात 2019 बैच की महिला कांस्टेबल प्रियंका ने जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर उसे सैफई मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया।

जानकारी के अनुसार, मूल रूप से सहारनपुर की रहने वाली प्रियंका इटावा पुलिस लाइन में रह रही थी। रविवार को पुलिस लाइन में ही उसने जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने के बाद उसे तत्काल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।

सैफई मेडिकल कॉलेज में मौत

सैफई मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर डॉक्टरों ने प्रियंका को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को मेडिकल कॉलेज के शवगृह में रखवा दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मेडिकल कॉलेज पहुंचे और मामले की जांच-पड़ताल की, लेकिन अधिकारियों ने घटना के कारणों को लेकर फिलहाल कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है।

प्रियंका ने किन परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ खाया, इसका अभी पता नहीं चल सका है। आत्महत्या के पीछे पारिवारिक, व्यक्तिगत या कोई अन्य कारण था, इसकी भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रियंका की दो बेटियां होने की जानकारी सामने आई है, जबकि उसके पति और परिवार से जुड़ी अन्य जानकारी अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है।

आज पोस्टमार्टम की संभावना

फिलहाल प्रियंका का शव सैफई मेडिकल कॉलेज के शवगृह में रखा गया है। अनुमान है कि सोमवार यानी आज दोपहर इटावा मुख्यालय में शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही महिला कांस्टेबल की मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच में जुटी हुई है।

2 जुलाई को भी हुई थी आत्महत्या

पुलिस लाइन में इससे पहले 2 जुलाई को एक सिपाही की पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। उस घटना के करीब एक महीने बाद अब महिला कांस्टेबल की आत्महत्या का मामला सामने आया है। लगातार सामने आई इन दोनों घटनाओं से पुलिस लाइन में रहने वाले पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों से जुड़े सुरक्षा एवं परिस्थितियों को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि, दोनों घटनाओं के बीच किसी संबंध की पुष्टि नहीं हुई है।

कांग्रेसियों ने पूर्व सांसद स्व . राम सिंह की मनाई नौवीं पुण्यतिथि, दी श्रद्धांजलि

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। पूर्व सांसद एवं विधायक स्व. राम सिंह की नौवीं पुण्यतिथि सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा सहित पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनके छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। कार्यक्रम के बाद संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने स्व. राम सिंह के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि स्व. राम सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन में जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता दी और क्षेत्र के लोगों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई। उनके योगदान और संघर्षों को याद करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने कहा कि स्व. राम सिंह का पूरा जीवन

जनसेवा के लिए समर्पित रहा। उन्होंने हमेशा समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों की आवाज को मजबूती से उठाया। उनके विचार और जनसेवा की भावना आज भी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं। पूर्व प्रदेश सचिव रणजीत सिंह सलूजा ने कहा कि स्व. राम सिंह का व्यक्तित्व संघर्ष, सादगी और जनसेवा का प्रतीक था। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस मौके पर वरिष्ठ नेता लाल पद्माकर सिंह, नफीस फारूखी, आवेश अहमद, ममनून आलम, शाहबाज खान, अतीक अहमद, सुब्रत सिंह सनी,शीतला साहू आदि लोग मौजूद रहे।

सफाई कर्मचारियों द्वारा मृतक सफाई कर्मचारी की पत्नी को 130000 आर्थिक मदद दी

आर्यावर्त संवाददाता

भदैया/सुलतानपुर। भदैया ब्लॉक के पंचायत राज विभाग में कार्यरत सुरेश कुमार का कुछ दिन पहले हार्ट अटैक से मृत्यु होने के कारण उनके परिवार में बहुत आर्थिक तंगी चल रही थी। पंचायत राज विभाग के कर्मचारियों द्वारा उनकी आर्थिक तंगी दूर करने के लिए अपने विभाग के द्वारा चंदा इकट्ठा कर मृतक सुरेश कुमार के पत्नी को सौंपा गया। इस पैसों से मृतक के परिवार को आर्थिक मदद मिलेगी भदैया ब्लॉक के ए डी ओ पंचायत अरविंद श्रीवास्तव के हाथों द्वारा इकट्ठा की गई रकम को मृतक सुरेश कुमार की पत्नी को दिया गया। यह पहेल पंचायत विभाग के सफाई कर्मचारी हृदय राम यादव द्वारा शुरू की गई। धीरे-धीरे यह मुहिम सभी कर्मचारियों के दिल और दिमाग में इस प्रकार बैठीं कि अपना परिवार नजर आने लगा। इस मुहिम में पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष सफाई कर्मचारी कमलेश कुमार यादव, संजय गुप्ता, सुरेंद्र कुमार तिवारी, पुष्पेंद्र पाल, प्रदीप यादव, बलराम यादव, रामकुमार यादव आदि लोगों ने अपना सहयोग दिया।

दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत में शिक्षक की मौत, युवक गंभीर

सुल्तानपुर। कूरेभार-फुलौना मार्ग पर सोमवार सुबह करीब नौ बजे बंदरहा गांव के पास दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत में एक शिक्षक की मौत हो गई, जबकि दूसरा बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कूरेभार पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने एक को मृत घोषित कर दिया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज सुलतानपुर रेफर किया गया। जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के केवटिया पीढ़ी निवासी सुरेश कुमार निषाद (38) सोमवार सुबह कूरेभार सब्जी मंडी से सब्जी बेचकर बाइक से घर लौट रहे थे। बंदरहा गांव के पास सामने से आ रही बाइक से उनकी भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइकें क्षतिग्रस्त हो गईं और सुरेश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में शहनवा, गोसाईंसिंहपुर-दोस्तपुर निवासी रजनीश कुमार (20) गंभीर रूप से घायल हो गए।

घर में धो रही थी बर्तन . . . तभी सांप ने हाथ में डसा, गाजियाबाद में 15 साल की साक्षी की मौत

आर्यावर्त संवाददाता

गाजियाबाद। गाजियाबाद कमिश्नरी के मसूरी थाना क्षेत्र के गांव बयाना में रविवार की रात एक सांप ने 15 वर्षीय लड़की को हाथ में डंस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक किशोरी का नाम साक्षी बताया जा रहा है। पड़ोस में रहने वाले एक समाज सेवी अरुण चंद्र ने जानकारी देते हुए बताया रविवार की रात लगभग 8:30 बजे गांव निवासी कल्लू की बेटी साक्षी अपने घर में जूठे बर्तन साफ कर रही थी। तभी कहीं से काले रंग का सांप आया और उसने उसके हाथ में डस लिया। अरुण चंद्र ने बताया कि सांप द्वारा डसने की जानकारी जैसे ही लड़की के परिवार वालों को पता चली तो उसे इलाज के लिए अलग-अलग निजी अस्पतालों में लेकर गए, लेकिन सभी जगह चिकित्सकों ने साक्षी को मृत घोषित कर दिया। साक्षी

की मां भी लगभग 15 वर्ष पहले सांप के डसने के कारण मौत हो गई थी। दरअसल, सावन का महीना है, जिसमें नाग देवता को पूजा जाता है। उनको भगवान शंकर के गले का हार भी कहा जाता है, लेकिन पिछले 15 दिनों में भगवान शंकर के गले के इस सर्पहार ने 18 लोगों को डस लिया है।

इनमें से समय पर इलाज मिलने से 12 लोगों की जान बच चुकी है। वहीं अस्पताल पहुंचने में देरी करने के कारण चार लोगों की मौत भी जा चुकी है। मिली जानकारी के मुताबिक, किसी का भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। सांप काटने से मरने वाले लोगों में एक कोतवाली थाना क्षेत्र के केला भट्टा का माली है, तो दो कावड़ियों की शिविर में सांप के काटने से मौत होने की बात कही जा रही है।

बारिश में गड्ढों से निकल आते हैं सांप

गाजियाबाद के जिला पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसपी पांडे ने बताया कि बारिश के मौसम में गड्ढों में पानी भर जाने के कारण अपने आप को सुरक्षित स्थान की तलाश में ले जाने के लिए जमीन के नीचे से सांप बिच्छू आदि जहरीले जीव बाहर निकल आते हैं। फिर खेतों, झाड़ियों, नालियों और कॉलोनियों में उनकी मौजूदगी बढ़ जाती है। रात के अंधेरे में सांप दिखाई नहीं देते हैं, जिसके कारण सांप के डसने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। उन्होंने आगे बताया कि अगर किसी को सांप डस लेता है, तो उसे समय रहते अस्पताल लाना चाहिए। वक्त रहते अस्पताल लाने पर सांप के जहर को निसप्रभावी किया जा सकता है, जिससे व्यक्ति की जान बच जाती है।

'तिरंगा यात्रा अमर बलिदानियों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की अभिव्यक्ति'

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तिरंगा यात्रा केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि भारत के हुतात्माओं, अमर बलिदानियों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति सम्मान एवं कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। देश और प्रदेश के युवाओं को राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास तथा स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। मुख्यमंत्री सोमवार को 'हर घर तिरंगा अभियान-2026' के अंतर्गत गोरखपुर में नगर निगम पार्क स्थित अमर वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा से रेलवे स्टेशन के समीप महाराणा प्रताप की प्रतिमा तक निकाली गई तिरंगा यात्रा में शामिल होने से पूर्व आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इससे पूर्व उन्होंने जनसेवा के लिए समर्पित एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि तिरंगा भारत की आन-बान-शान का प्रतीक है। देश की आजादी के आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अलग-अलग समय में विभिन्न प्रकार के ध्वजों के माध्यम से आंदोलन को नई गति प्रदान की। वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन भारत की आजादी का मंत्र बना। इसके बाद 1930 के दशक में तिरंगे के मध्य चरखे का चिन्ह स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ध्वज का प्रतीक बना। स्वतंत्र भारत में तिरंगे के साथ धर्मचक्र को स्थान दिया गया और राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया।योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि जिस राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के लिए पहले भारत के नागरिकों को न्यायालय में संघर्ष करना पड़ता था, आज प्रत्येक नागरिक को सम्मानपूर्वक अपने घर पर तिरंगा फहराने का अधिकार प्राप्त है। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान वर्ष 2022 में राष्ट्रीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया, जिसके बाद कोई भी नागरिक सम्मानजनक ढंग से अपने घर पर तिरंगा फहरा सकता है।उन्होंने कहा कि 'हर घर तिरंगा' प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके माध्यम से प्रत्येक नागरिक अपने घर पर तिरंगा फहराकर गौरव की अनुभूति कर सकता है। वर्ष 2022, 2023, 2024 और 2025 के बाद वर्ष 2026 में भी तिरंगा यात्रा के साथ 'हर घर तिरंगा' अभियान व्यापक जनभागीदारी की ओर बढ़ रहा है। तिरंगे के प्रति जागरूकता और राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करने के लिए प्रदेशभर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, जिनमें हजारों की संख्या में युवा हाथों में तिरंगा लेकर राष्ट्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त कर रहे हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र के महापुरुष और क्रांतिकारी प्रत्येक युवा के लिए प्रेरणास्रोत होते हैं। तिरंगा भारत के क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान की अमिट गाथा का प्रतीक है। किसी युवा से उसके आदर्श को छीनना उसे गौरव के भाव से वंचित करने के समान है। युवाओं को राष्ट्रगौरव की अनुभूति से जोड़ने के लिए 'हर घर तिरंगा' अभियान को व्यापक जनभागीदारी का स्वरूप दिया गया है।उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश हमेशा से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बिंदु रहा है। बैरकपुर में मंगल पांडे, गोरखपुर में शहीद बंधू सिंह, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिठूर-कानपुर में तात्या टोपे तथा मेरठ में धन सिंह कोतवाल ने स्वतंत्रता की जो चिंगारी प्रज्ज्वलित की थी, वह प्रत्येक जनपद और गांव तक पहुंची तथा भारत की आजादी का मंत्र बनी।

हमें अचानक नहीं मिली, बल्कि इसके लिए देशवासियों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। वर्ष 1922 की चौरी-चौरा की ऐतिहासिक घटना ने अंग्रेजी शासन की चूलें हिला दी थीं।योगी आदित्यनाथ ने कहा कि काकोरी ट्रेन एक्शन भी भारत की आजादी का मंत्र था। वर्ष 1925 में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, शचीन्द्रनाथ सान्याल और राजेन्द्र नाथ लाहिड़ी सहित अनेक क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों द्वारा भारत से लूटकर ब्रिटेन ले जाए जा रहे धन को वापस लेकर उसे देश की आजादी के लिए उपयोग करने का कार्य किया। इसी उद्देश्य से काकोरी ट्रेन एक्शन की ऐतिहासिक घटना को अंजाम दिया गया।मुख्यमंत्री ने कहा कि अंग्रेजों ने काकोरी ट्रेन एक्शन को 'डकैती' कहा था और देश की आजादी के बाद भी लंबे समय तक काकोरी की घटना को इसी दृष्टिकोण से पढ़ाया जाता रहा। अब काकोरी की घटना को 'काकोरी ट्रेन एक्शन' के रूप में प्रतिष्ठित करते हुए क्रांतिकारियों के योगदान को उचित सम्मान दिया जा रहा है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां और राजेन्द्र नाथ लाहिड़ी सहित अनेक क्रांतिकारियों ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। अलग-अलग स्थानों की जेलों में इन अमर बलिदानियों को फांसी दी गई।उन्होंने कहा कि आजादी के बाद लंबे समय तक इन क्रांतिकारियों को वह सम्मान नहीं मिला, जिसके वे हकदार थे। उनकी प्रतिमाएं स्थापित नहीं की जाती थीं और उनके नाम पर सड़कों एवं संस्थाओं के नाम रखने में भी उपेक्षा की गई। अब इन अमर क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को उचित सम्मान दिया जा रहा है।मुख्यमंत्री ने युवाओं का आह्वान किया कि वे 'हर घर तिरंगा अभियान' के अंतर्गत निकलने वाली तिरंगा यात्राओं में उत्साहपूर्वक भाग लें और अपनी सहभागिता से संबंधित सेल्फी अपलोड करें। सरकार ने इस वर्ष उत्तर प्रदेश में पांच करोड़ घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रत्येक सरकारी, अर्द्धसरकारी एवं निजी संस्थान, उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा घरों में तिरंगा फहराया जाएगा।उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और क्रांतिकारियों ने जाति-पांति का विचार किए बिना राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। महान क्रांतिकारियों ने राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ कार्य किया। हम सभी तिरंगा, वंदे मातरम् और राष्ट्रगान का सम्मान करके उन क्रांतिकारियों तथा अपनी गौरवशाली विरासत का सम्मान कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और उसके राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान प्रत्येक नागरिक का दायित्व होना चाहिए।

प्रदेश के सभी 762 नगरीय निकायों में लागू होगी एकमुश्त समाधान योजना

लखनऊ। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के नगरीय निकायों में लंबे समय से लंबित संपत्ति कर यानी गृहकर, जलकर और सीवरकर की प्रभावी वसूली, करदाताओं को व्यावहारिक राहत देने, न्यायालयों में चल रहे विवादों को कम करने तथा नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति को और मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी 762 नगरीय निकायों में एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू करने का निर्णय लिया है।इस योजना का लाभ प्रदेश के 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतों में लंबित संपत्ति कर के बकायेदार करदाताओं को मिलेगा। योजना के माध्यम से लंबे समय से लंबित कर बकायों के समाधान का रास्ता आसान होगा और करदाताओं को एकमुश्त आर्थिक बोझ से राहत मिल सकेगी।

तीन मकानों में चोरी करने वाले गिरोह के तीन सदस्य गिरफ्तार, जेवरात, नकदी और तार बरामद

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। गोमतीनगर और गोमतीनगर विस्तार क्षेत्र में मकानों में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पीली व सफेद धातु के आभूषण, 8,100 रुपये नकद, करीब 2.6 किलोग्राम बिजली के तार तथा वारदात में प्रयुक्त अपाचे मोटरसाइकिल बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों में मोनू गौतम, रामदयाल साहनी और विशाल रावत शामिल हैं।पुलिस के अनुसार, गोमतीनगर विस्तार थाने में 29 जुलाई 2026 की रात विज्ञानखंड निवासी ऊषा कुमारी के मकान की खिड़की तोड़कर घर में घुसने और कीमती जेवरात व नकदी चोरी किए जाने का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके अलावा 15 जून को सेक्टर-5 गोमतीनगर विस्तार निवासी प्रांजल त्रिपाठी के मकान का ताला तोड़कर वायरिंग का तार चोरी करने तथा 8 अगस्त की रात विनीतखंड गोमतीनगर निवासी सूरज सिंह के मकान से लेनोवो लैपटॉप, चार्जर, बैग, चांदी की मूर्ति और नकदी चोरी किए जाने के मामले भी दर्ज थे।पुलिस ने इन घटनाओं की जांच के दौरान सुरागरसी-पतारसी और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर तीनों आरोपियों को 10 अगस्त 2026 की रात करीब 1:40 बजे गोमतीनगर विस्तार थाना क्षेत्र के सेक्टर-4 स्थित ईदगाह के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोनू गौतम पुत्र दन्नू, निवासी जहांगीरपुरी, नई दिल्ली, हाल निवासी लक्ष्मणपुरी, थाना गाजीपुर, लखनऊ, उम्र करीब 40 वर्ष, रामदयाल साहनी पुत्र मजनू साहनी, निवासी सीतामढ़ी, बिहार, हाल निवासी विजय बिहार, तकरोही, थाना इंदिरानगर, लखनऊ, उम्र करीब 31 वर्ष तथा विशाल रावत पुत्र रामपाल रावत, निवासी कठौता, विजयंतखंड, थाना विभूतिखंड, लखनऊ, उम्र करीब 25 वर्ष के रूप में हुई है।पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के कब्जे से चार पतले और दो चौड़े पीली धातु के कंगन, दो मंगलसूत्र के लॉकेट, एक जोड़ी पुरानी बिछिया, एक पायल, काले, नीले, सफेद और लाल रंग के करीब 2.6 किलोग्राम तार, 8,100 रुपये नकद तथा वारदात में प्रयुक्त नीले रंग की अपाचे मोटरसाइकिल संख्या यूपी 32 एलजे 9318 बरामद हुई है।

प्रदेश के पर्यटन स्थलों के विकास पर 1198 करोड़ रुपये से अधिक खर्च, 575 परियोजनाओं को मिली मंजूरी

लखनऊ। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य सेक्टर के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पर्यटन स्थलों पर पर्यटन सुविधाओं के सृजन एवं विकास के लिए 1198 करोड़ 41.10 लाख रुपये की 575 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश के प्रमुख धार्मिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन स्थलों पर व्यापक स्तर पर विकास कार्य कराए जा रहे हैं।यह जानकारी प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि स्वीकृत धनराशि से आगरा, लखनऊ, फर्रुखाबाद, महोबा, सीतापुर, वाराणसी, हापुड़, फिरोजाबाद, बलिया, बदायूं, बस्ती, बिजनौर, कन्नौज, कासगंज, मथुरा, मेरठ और संतकबीरनगर सहित प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।

संक्षेप

बीबीएयू में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए 11 से 18 अगस्त तक पंजीकरण

लखनऊ। बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू) में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के विभिन्न पाठ्यक्रमों में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए सीयूईटी और गैर-सीयूईटी अभ्यर्थियों की पंजीकरण प्रक्रिया 11 से 18 अगस्त 2026 तक चलेगी। विश्वविद्यालय की ओर से जारी प्रवेश काउंसलिंग कार्यक्रम के अनुसार रिक्त सीटों पर प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में पंजीकरण करा सकेंगे।विश्वविद्यालय में द्वितीय स्पॉट काउंसलिंग 19 अगस्त 2026 को आयोजित की जाएगी। स्पॉट काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। पात्र पाए जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश शुल्क जमा करने हेतु चालान जनरेट किया जाएगा। द्वितीय स्पॉट काउंसलिंग में चयनित अभ्यर्थियों को 23 अगस्त 2026 तक प्रवेश शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, जिन अभ्यर्थियों ने पहले ही किसी अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया है, वे भी रिक्त सीटों पर उपलब्ध अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी अपनी रुचि और निर्धारित पात्रता के अनुसार उपलब्ध पाठ्यक्रमों के लिए तय अवधि में पंजीकरण करा सकेंगे।विश्वविद्यालय ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि रिक्त सीटों, पात्रता, पंजीकरण प्रक्रिया और काउंसलिंग से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी अधिसूचनाओं का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें।

आईटीआई में विकल्प परिवर्तन के लिए 12 अगस्त तक पोर्टल खुला

लखनऊ। प्रदेश के राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रशिक्षण लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों को विकल्प परिवर्तन का अवसर दिया गया है। अभ्यर्थी 9 से 12 अगस्त 2026 तक एससीवीटी पोर्टल के माध्यम से संस्थान अथवा व्यवसाय का विकल्प बदल सकेंगे।व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रदेश के राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित विभिन्न व्यवसायों के साथ-साथ टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से 211 राजकीय संस्थानों में संचालित 10 दीर्घकालीन व्यवसायों में भी प्रवेश के लिए विकल्प परिवर्तन किया जा सकेगा। इसके अलावा पीपीपी मॉडल पर संचालित राजकीय संस्थानों के विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण के लिए भी अभ्यर्थियों को संस्थान अथवा व्यवसाय का विकल्प बदलने की सुविधा दी गई है।विभाग ने अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए 9 अगस्त से 12 अगस्त 2026 तक एससीवीटी पोर्टल को विकल्प परिवर्तन के लिए खोलने का निर्णय लिया है। अभ्यर्थी निर्धारित अवधि के भीतर अपनी पसंद के संस्थान और व्यवसाय का विकल्प चुन सकते हैं।विभाग ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर विकल्प परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि प्रवेश प्रक्रिया में उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

चकबंदी के लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी, 11 गांवों को प्रक्रिया से किया गया पृथक

लखनऊ। मुख्यमंत्री के निर्देश पर चकबंदी प्रक्रिया के अंतर्गत लंबे समय से लंबित गांवों के मामलों के शीघ्र निस्तारण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। इसका उद्देश्य किसानों को समय से सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के साथ ही उनकी जमीन से जुड़े मामलों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है।चकबंदी आयुक्त डॉ. ऋषिकेश भास्कर यशोद ने बताया कि प्रदेश के कुछ गांवों में विकास योजनाओं, नदी कटान, 40 प्रतिशत से कम चकबंदी योग्य क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र में शामिल होने तथा गुटबंदी जैसे कारणों से चकबंदी की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही थी। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए जोत चकबंदी अधिनियम की धारा-6(1) के तहत सात जनपदों के 11 गांवों को चकबंदी प्रक्रिया से पृथक किया गया है।इनमें चित्रकूट जनपद के अग्रहुंडा, औरा, पिलखिनी तथा तेरा बुजुर्ग में पिछले 12 वर्षों से चकबंदी प्रक्रिया लंबित थी। इसी प्रकार रायबरेली के अटौरा बुजुर्ग और हापुड़ के इकलेड़ी गांव में 11 वर्षों से प्रक्रिया लंबित थी। संतकबीर नगर के जसौवर, तप्पा-फिदाईपुर, सलहाबाद तथा तप्पा-तरयापार में 10 वर्षों से, एटा के बरिगवां और प्रतापगढ़ के जगदीशपुर में नौ वर्षों से तथा गोरखपुर के टड़वा श्रीराम गांव में दो वर्षों से चकबंदी प्रक्रिया चल रही थी।चकबंदी आयुक्त ने बताया कि विशेष प्रयासों के माध्यम से प्रदेश के तीन गांवों में चकबंदी प्रक्रिया पूर्ण कराई गई है। इसके तहत अम्बेडकरनगर के पीठापुर आशाजीतपुर, ललितपुर के बरौनी नकीब तथा लखनऊ के शाहपुर राजा में जोत चकबंदी अधिनियम की धारा-52(1) के अंतर्गत चकबंदी प्रक्रिया पूरी कर दी गई है।उन्होंने बताया कि लखनऊ के शाहपुर राजा गांव में चकबंदी का कार्य महज दो वर्ष में पूरा किया गया।

दिव्यांगजन रोजगार अभियान-3 .0 की अवधि बढ़ी

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तत्वावधान में दिव्यांगजनों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आयोजित किए जा रहे दिव्यांगजन रोजगार अभियान-3.0 की समय-सीमा बढ़ा दी गई है। पहले यह अभियान 3 से 10 अगस्त 2026 तक निर्धारित था, जिसे जनहित को ध्यान में रखते हुए अब 13 अगस्त 2026 तक संचालित करने का निर्णय लिया गया है।मिशन निदेशक पुलकित खरे ने बताया कि इस महत्वपूर्ण पहल का मुख्य उद्देश्य निर्धारित रोजगार लक्ष्यों को शत-प्रतिशत पूरा करना और प्रदेश के अधिक से अधिक दिव्यांग युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों से जोड़कर लाभान्वित करना है। अभियान को मिल रहे सकारात्मक रुझान और इसमें पंजीकरण कराने वाले अभ्यर्थियों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए इसकी अवधि बढ़ाई गई है।उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत दिव्यांग अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता, क्षमता और रुचि के अनुसार रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए विभिन्न निजी कंपनियों और कौशल विकास से जुड़ी संस्थाओं का सहयोग लिया जा रहा है। अभियान के माध्यम से पात्र दिव्यांग युवाओं को रोजगार से जोड़ने के साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है।अभियान की विस्तारित अवधि को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों और जिला स्तरीय टीमों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे 13 अगस्त तक अभियान का सुचारु और प्रभावी संचालन सुनिश्चित करें तथा अधिक से अधिक पात्र दिव्यांग अभ्यर्थियों को योजना से जोड़ें।

सीईआईआर पोर्टल से ट्रेस कर गाजीपुर पुलिस ने बरामद किए 36 गुम मोबाइल

5.80 लाख रुपये के फोन मालिकों को सौंपे

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। गाजीपुर थाना पुलिस की साइबर हेल्पडेस्क टीम ने तकनीकी निगरानी और सीईआईआर पोर्टल की मदद से विभिन्न स्थानों से गुम एवं खोए हुए 36 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बरामद मोबाइल फोनों की अनुमानित कीमत करीब 5.80 लाख रुपये बताई गई है। आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुलिस ने सभी मोबाइल उनके वास्तविक स्वामियों को सौंप दिए।पुलिस के अनुसार, पुलिस उपायुक्त पूर्वी के पर्यवेक्षण, अपर पुलिस उपायुक्त पूर्वी एवं सहायक पुलिस आयुक्त गाजीपुर के निर्देशन तथा प्रभारी निरीक्षक गाजीपुर राजेश कुमार मौर्य के नेतृत्व में साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा गुम और खोए मोबाइल फोनों की लगातार तकनीकी निगरानी एवं ट्रेसिंग की जा रही थी। इसी क्रम में सीईआईआर (सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर) पोर्टल का प्रभावी उपयोग करते हुए गाजीपुर थाने पर दर्ज विभिन्न मामलों में गुम हुए मोबाइल फोनों की तकनीकी जानकारी जुटाई गई।पुलिस टीम ने मोबाइल फोन के उपयोग एवं स्थान से संबंधित प्राप्त तकनीकी विवरण का विश्लेषण कर अलग-अलग स्थानों से कुल 36 मोबाइल बरामद किए। इनमें कुछ मोबाइल फोन ऐसे भी शामिल हैं, जो वर्ष 2023 और 2024 में गुम हुए थे। लंबे समय बीत जाने के बाद भी साइबर हेल्पडेस्क की लगातार तकनीकी निगरानी और सीईआईआर पोर्टल पर उपलब्ध सूचनाओं के विश्लेषण के आधार पर इन मोबाइलों को ट्रेस कर बरामद किया गया।बरामद मोबाइल फोनों में ओप्पो, वीवो, सैमसंग, मोटोरोला, वनप्लस, रियलमी, रेडमी, पोको, लावा और आईटेल सहित विभिन्न कंपनियों के मोबाइल शामिल हैं। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद मोबाइल स्वामियों को थाना गाजीपुर बुलाकर उनके फोन सुपुर्द किए गए।लंबे समय बाद अपना खोया हुआ मोबाइल वापस पाकर मोबाइल स्वामियों ने खुशी जताई और गाजीपुर थाना पुलिस, साइबर हेल्पडेस्क टीम तथा लखनऊ पुलिस की कार्रवाई की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया।मोबाइल बरामद करने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक अभिषेक वर्मा, सहायक उपनिरीक्षक एवं कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-'बी' आमिर अली खान, कांस्टेबल गौरव शर्मा तथा महिला कांस्टेबल पूजा शर्मा शामिल रहीं।

डॉ. सूर्यकान्त को इंडियन सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्स एंड बायोलॉजिस्ट्स (आईएससीबी) एक्सीलेंस अवार्ड फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट इन मेडिकल साइंसेज से किया गया सम्मानित

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. सूर्यकान्त को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए आईएससीबी एक्सीलेंस अवार्ड फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट इन मेडिकल साइंसेज बाय इंडियन सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्स एंड बायोलॉजिस्ट्स (आईएससीबी) एंड आईएससीबी रिसर्च फाउंडेशन द्वारा सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर प्रभाव डालने वाले महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किया जाता है।

इंडियन सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्स एंड बायोलॉजिस्ट्स (आईएससीबी) की स्थापना वर्ष 1995 में सीडीआरआई, लखनऊ में रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्विषयक शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। वर्तमान में इसके लगभग 1,800 सदस्य हैं, जो शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी संगठनों और उद्योग जगत से जुड़े हुए हैं। आईएससीबी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, वैज्ञानिक व्याख्यानों और शोध गतिविधियों के माध्यम से विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देता है। संस्था द्वारा उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक गतिविधियों को मजबूत करना तथा देश-विदेश के विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं को एक मंच पर लाना है। फाउंडेशन शोध, नवाचार, वैज्ञानिक सहयोग और ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहा है। आईएससीबी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. अनामिक शाह एवं राष्ट्रीय सचिव डॉ. पी एम एस चैहान ने डा0 सूर्यकान्त को इस प्रतिस्थित अवार्ड के लिए बधाई दी है और आशा की है कि वे इस संस्था को भी अपना मार्गदर्शन प्रदान करेंगें।

ज्ञात रहे कि डॉ. सूर्यकान्त विश्व के सर्वोच्च 2 प्रतिशत वैज्ञानिकों की श्रेणी में भी शमिल हैं। वह रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग में विगत 30 वर्षों से चिकित्सा शिक्षक, 21 वर्षों से प्रोफेसर व 15 वर्षों से विभागाध्यक्ष के पद सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा वह चिकित्सा विज्ञान सम्बंधित विषयों पर 25 किताबें भी लिख चुके हैं तथा एलर्जी, अस्थमा, टी.बी. एवं कैंसर के क्षेत्र में उनके अब तक लगभग 1000 से अधिक शोध पत्र राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं साथ ही 2 अंतर्राष्ट्रीय पेटेन्ट का भी उनके नाम श्रेय जाता है। लगभग 250 एमडी/पीएचडी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन, 50 से अधिक शोध परियोजनाओं का निर्देशन, 22 फैलोशिप, 22 ओरेशन एवार्ड का भी श्रेय उन्हें जाता है। उन्हें अब तक अन्तरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर की विभिन्न संस्थाओं द्वारा 231 पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। यह उनका 232वाँ अवार्ड है। डॉ. सूर्यकान्त ने कहा कि यह सम्मान केवल उनका व्यक्तिगत सम्मान नहीं, बल्कि यह रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग, केजीएमयू तथा उन सभी सहयोगियों और शोधकर्ताओं के प्रयासों का सम्मान है, जिन्होंने चिकित्सा एवं शोध के क्षेत्र में निरंतर सहयोग किया है। यह सम्मान मुझे मरीजों की बेहतर सेवा, चिकित्सा शिक्षा और शोध के क्षेत्र में और अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। डॉ. सूर्यकान्त पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से अपने लेखों व वार्ताओ एवं टी.वी. व रेडियों एवं इलेक्ट्रानिक/प्रिंट/सोशल मीडिया के माध्यम से लोगो में टी.बी. रोग, अस्थमा, एलर्जी, लंग कैंसर व श्वसन संबंधी अन्य बीमारियों से बचाव व उपचार के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं। नई शिक्षा नीति की तीसरी वर्षगांठ पर पीएम श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी हिंदी में 100 पुस्तकों का विमोचन किया गया उसमें डा0 सूर्यकान्त की 2 पुस्तकें 'टीबी' एवं 'आस्थमा में योग की भूमिका' हिन्दी में पुस्तक भी शामिल है। समय समय पर आम जनमानस के लिए इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी टीबी रोग के लेख, वार्ता, वीडियों आदि के द्वारा जागरूक करते रहते है। डॉ. सूर्यकान्त वर्तमान में केजीएमयू के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष एवं केजीएमयू की कार्य परिषद के सदस्य हैं। वर्तमान में वे गवर्निंग बॉडी एम्स भुवनेश्वर तथा यू.पी. यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल सांइन्सेज, सैफई, इटावा के एकेडमिक काउंसिल के सदस्य भी है। वे पूर्व में लखनऊ विश्वविद्यालय के कार्य परिषद के सदस्य रहे हैं। इसके साथ ही वे यू.पी. यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल सांइन्सेज, सैफई, इटावा की कार्य परिषद के सदस्य भी रहे हैं। वे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के इन्स्टीट्यूट एवं गवर्निंग बॉडी एवं बोर्ड ऑफ मैनेजमेन्ट, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर के सदस्य एवं स्टैंडिंग सेलेक्शन कमेटी के चेयरमैन भी रहें हैं।

लखनऊ विश्वविद्यालय में विपश्यना के दार्शनिक अध्ययन पर शोध कार्य पूर्ण

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के संस्कृत एवं प्राकृत भाषा विभाग में पोस्ट डॉक्टोरल फेलो डॉ. सीता देवी ने 'विपश्यना का विसुद्धिमग्ग में दार्शनिक अध्ययन' विषय पर अपना शोध कार्य पूर्ण किया। यह शोध कार्य शोध निर्देशक डॉ. बृजेश कुमार सोनकर के निर्देशन में संपन्न हुआ।शोध कार्य के अंतर्गत डॉ. सीता देवी ने विसुद्धिमग्ग में वर्णित विपश्यना के विभिन्न दार्शनिक एवं व्यावहारिक पक्षों का अध्ययन किया। शोध के प्रस्तुतीकरण के दौरान उन्होंने विशेष रूप से शील, समाधि और प्रज्ञा जैसे त्रिरत्नों की सामाजिक, नैतिक एवं शैक्षिक उपयोगिता पर प्रकाश डाला।शोध प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि विपश्यना केवल आध्यात्मिक साधना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से व्यक्ति में चारित्रिक विकास, आत्मानुशासन, मानसिक एकाग्रता और सकारात्मक जीवन-दृष्टि जैसी क्षमताओं का विकास किया जा सकता है। आधुनिक सामाजिक परिवेश में इन गुणों को व्यक्ति और समाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकता बताते हुए शोध में विपश्यना की प्रासंगिकता को रेखांकित किया गया।डॉ. सीता देवी ने शोध प्रस्तुतीकरण के दौरान विपश्यना की दार्शनिक अवधारणाओं और वर्तमान समय में उनकी उपयोगिता पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि प्राचीन भारतीय चिंतन परंपरा में वर्णित साधना पद्धतियां आज भी व्यक्ति के नैतिक एवं मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।शोध ग्रंथ के प्रस्तुतीकरण के अवसर पर संस्कृत एवं प्राकृत भाषा विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. अभिमन्यु सिंह सहित विभाग के सभी शिक्षक उपस्थित रहे।

संसदीय-गतिरोध से नहीं चलेगा लोकतंत्र, संवाद ही है समाधान

भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति उसकी संसद है। यही वह सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच है जहां राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य से जुड़े विषयों पर गंभीर विमर्श होता है, सरकार जवाबदेह बनती है, विपक्ष जनभावनाओं को स्वर देता है और कानूनों के माध्यम से देश के विकास की दिशा तय होती है। लेकिन अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज संसद संवाद और सहमति का मंच बनने के बजाय टकराव, आरोप-प्रत्यारोप, नारेबाजी और राजनीतिक हठधर्मिता का अखाड़ा बनती जा रही है। मानसून सत्र में जिस प्रकार लगातार गतिरोध बना हुआ है, उससे केवल संसदीय कार्यवाही ही बाधित नहीं हो रही, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा भी आहत हो रही है। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजीजू और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच गतिरोध समाप्त करने के लिए हुई बातचीत भी किसी ठोस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकी। यह स्थिति बताती है कि दोनों पक्ष अपने-अपने राजनीतिक आग्रहों में इतने उलझ गए हैं कि राष्ट्रहित पीछे छूट गया है। विपक्ष की ओर से यह शर्त रखी जा रही है कि जब तक कुछ विशेष मुद्दों पर सरकार सदन में बयान और चर्चा के लिए तैयार नहीं होती, तब तक संसद की कार्यवाही नहीं चलने दी जाएगी। दूसरी ओर सरकार भी अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने पर अडिग है। परिणाम यह है कि संसद का बहुमूल्य समय निरर्थक विवादों की भेंट चढ़ रहा है।

लोकतंत्र में असहमति स्वाभाविक है, किंतु असहमति को अराजकता में बदल देना लोकतांत्रिक संस्कृति नहीं है। विपक्ष का दायित्व केवल विरोध करना नहीं, बल्कि रचनात्मक सुझाव देना भी है। सरकार को कठघरे में खड़ा करना विपक्ष का अधिकार है, परंतु संसद को ठप कर देना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। लोकतंत्र में विरोध की भी मर्यादा होती है। जब विरोध संसद को चलने ही न दे, तब वह लोकतांत्रिक अधिकार नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक दायित्वों की उपेक्षा बन जाता है। पिछले कुछ वर्षों से यह चिंताजनक प्रवृत्ति लगातार बढ़ी है कि संसद सत्र प्रारंभ होने से पहले ऐसे मुद्दे राजनीतिक रूप से उछाले जाते हैं, जिनके आधार पर पूरे सत्र को बाधित किया जा सके। परिणामस्वरूप अनेक महत्वपूर्ण विधेयक बिना पर्याप्त चर्चा के पारित हो जाते हैं अथवा कई विधेयक लंबित रह जाते हैं। इससे सबसे अधिक नुकसान देश को होता है। संसद का प्रत्येक मिनट करोड़ों रुपये की सार्वजनिक धनराशि से संचालित होता है। यदि वह समय केवल शोर-शराबे और नारेबाजी में बीत जाए तो यह करदाताओं के धन और लोकतांत्रिक विश्वास-दोनों का अपमान है।

लोकतंत्र में संवाद ही समाधान का सबसे प्रभावी माध्यम है। महात्मा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक भारतीय राजनीति की श्रेष्ठ परंपरा संवाद, सहमति और संवेदनशीलता की रही है। आज आवश्यकता इस बात की है कि पक्ष और विपक्ष दोनों अपने-अपने दुराग्रह छोड़कर संवाद की मेज पर बैठें। संसद की गरिमा इस बात में नहीं कि कौन किसे अधिक कठघरे में खड़ा करता है, बल्कि इस बात में है कि राष्ट्रहित के प्रश्नों पर कितनी गंभीरता से विचार किया जाता है। विशेष रूप से कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी को यह समझना होगा कि लोकतंत्र केवल आंदोलन और विरोध का नाम नहीं है। विपक्ष की भूमिका सरकार को गिराने की नहीं, बल्कि लोकतंत्र को संभालने की होती है। यदि प्रत्येक मुद्दे पर संसद को बाधित करने की रणनीति अपनाई जाएगी तो जनता के बीच यह संदेश जाएगा कि विपक्ष के पास वैकल्पिक नीति और दृष्टि का अभाव है। लोकतंत्र में जनता केवल विरोध नहीं, समाधान भी चाहती है। यदि विपक्ष स्वयं संवाद से दूरी बनाएगा तो 'संवाद से समाधान' का आदर्श केवल नारा बनकर रह जाएगा। सरकार की भी जिम्मेदारी कम नहीं है। लोकतंत्र में बहुमत का अर्थ मनमानी नहीं होता। सरकार को भी विपक्ष की उचित मांगों को सुनना चाहिए और जहां संभव हो, सहमति का मार्ग निकालना चाहिए। संसद किसी एक दल की नहीं, पूरे राष्ट्र की संस्था है। इसलिए सरकार को भी संवेदनशीलता, धैर्य और व्यापक दृष्टिकोण का परिचय देना होगा। किंतु यदि संवाद का प्रत्येक प्रयास केवल राजनीतिक शर्तों और हठधर्मिता में उलझ जाए तो समाधान की संभावनाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। आज सबसे बड़ी आवश्यकता राजनीतिक परिपक्वता की है। दुर्भाग्य से भारतीय राजनीति में आग्रह, पूर्वाग्रह और दुराग्रह का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। हर मुद्दे को चुनावी लाभ-हानि के चश्मे से देखा जा रहा है। संसद में बहस कम और राजनीतिक संदेश अधिक दिए जा रहे हैं। यह प्रवृत्ति लोकतंत्र को कमजोर करती है। संसद का उद्देश्य जनकल्याणकारी नीतियों पर विचार करना है, न कि चुनावी रणनीतियों का मंच बन जाना। देश आज आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति, रोजगार, शिक्षा, कृषि, राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और सामाजिक समरसता जैसी अनेक चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय संसद का प्रत्येक दिन अत्यंत मूल्यवान है। यदि यह समय केवल राजनीतिक टकराव में व्यतीत होगा तो विकास की गति अवश्य प्रभावित होगी। कानूनों में विलंब, नीतिगत निर्णयों की देरी और संसदीय अस्थिरता का सीधा प्रभाव आम नागरिक के जीवन पर पड़ता है।

आत्मनिर्भर चिकित्सा तकनीक: सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं और विकसित भारत की मजबूत नींव

जगत प्रकाश नड्डा

सिर्फ चिकित्सा उपकरणों का निर्माण केंद्र बनने के अलावा, भारत तेजी से आधुनिक चिकित्सा तकनीकों को अपना भी रहा है, ताकि लोगों का जीवन बेहतर बनाया जा सके

भारत ने पिछले एक दशक में स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में अभूतपूर्व विस्तार किया है। सरकारी और निजी क्षेत्र में अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, जांच केंद्रों और मेडिकल कॉलेजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। शहरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ है। यह सरकार की ऐसी नीतियों को दर्शाता है, जिनका केंद्र आम नागरिक की स्वास्थ्य सुरक्षा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को हर नागरिक तक पहुंचाने के लिए काम किया है। इन लगातार किए गए प्रयासों का परिणाम है कि देश में लोगों द्वारा अपनी जेब से स्वास्थ्य सेवाओं पर किए जाने वाले खर्च में पिछले कुछ वर्षों में बड़ी कमी आई है। यह खर्च पहले 65 प्रतिशत तक था, जो अब घटकर 43 प्रतिशत रह गया है।

जिला अस्पताल में जन्म लेने वाले नवजात शिशु से लेकर बड़े अस्पताल में इलाज करा रहे कैंसर मरीज तक, आधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में भरोसेमंद, अच्छी गुणवत्ता वाले और किफायती चिकित्सा उपकरण बेहद जरूरी हो गए हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत सरकार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत कर रही है। इसके लिए प्रयोगशालाओं को बेहतर बनाने, गंभीर मरीजों के इलाज की सुविधाएं बढ़ाने, बीमारियों की निगरानी व्यवस्था मजबूत करने और आपात स्थिति से निपटने की क्षमता बढ़ाने पर निवेश किया जा रहा है। जैसे-जैसे भारत 2047 तक विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, अब जोर एक आत्मनिर्भर चिकित्सा तकनीक क्षेत्र तैयार करने पर है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को और सस्ता, आसानी से उपलब्ध और किसी भी संकट के समय मजबूत बनाना है।

पहले ,भारत कई आधुनिक और जटिल चिकित्सा उपकरणों के लिए काफी हद तक दूसरे देशों से होने वाले आयात पर निर्भर था। इन तकनीकों से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार तो हुआ, लेकिन इससे इलाज की लागत बढ़ी, आपूर्ति व्यवस्था पर बाहरी निर्भरता बनी रही और इन उपकरणों की पहुंच सीमित रही। इसी जरूरत को देखते हुए राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, 2023 में देश के भीतर आधुनिक चिकित्सा उपकरण बनाने की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसका उद्देश्य चिकित्सा उपकरणों को सस्ता बनाना और जांच की लागत कम करना है। सरकार ने चिकित्सा उपकरणों के पूरे क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, चिकित्सा उपकरण पार्क और दवा एवं चिकित्सा तकनीक के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने वाली योजना शामिल हैं।

इन पहलों से देश में चिकित्सा उपकरणों के निर्माण, नए शोध, निवेश और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए बेहतर माहौल तैयार हो रहा है। नतीजे उत्साह बढ़ाने वाले हैं। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 50 से अधिक आधुनिक चिकित्सा उपकरणों का देश में उत्पादन शुरू हो चुका है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में विदेशी निवेश लगातार बढ़ रहा है, जो वैश्विक निवेशकों के बढ़ते भरोसे को दर्शाता है। ये उपलब्धियां बताती हैं कि भारत धीरे-धीरे दुनिया के चिकित्सा तकनीक क्षेत्र में एक भरोसेमंद भागीदार के रूप में उभर रहा है।

सिर्फ चिकित्सा उपकरणों का निर्माण केंद्र बनने के अलावा, भारत तेजी से आधुनिक चिकित्सा तकनीकों को अपना भी रहा है, ताकि लोगों का जीवन बेहतर बनाया जा सके। आधुनिक जांच सुविधाओं, शरीर की अंदरूनी तस्वीर लेने वाली मशीनों, शरीर में लगाए जाने वाले चिकित्सा उपकरणों, गहन चिकित्सा की मशीनों और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को किफायती दर पर उपलब्ध कराने से मरीजों पर इलाज का आर्थिक बोझ कम होता है। साथ ही इलाज की गुणवत्ता और समय पर इलाज मिलने में भी सुधार होता है। देश में ही चिकित्सा उपकरण बनने से विदेशों से आयात पर निर्भरता घटती है, आपूर्ति व्यवस्था मजबूत होती है और लागत कम करने के अवसर बढ़ते हैं।

भारत का विश्व स्तर पर पहचान बना चुका दवा उद्योग, मजबूत इंजीनियरिंग क्षमता, तेजी से फैलता डिजिटल ढांचा, तेजी से बढ़ता नए उद्यमों का क्षेत्र और कुशल मानव संसाधन अगली पीढ़ी की चिकित्सा तकनीक विकसित करने के लिए मजबूत आधार प्रदान करते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, चिकित्सा उपकरण के रूप में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर (एसएमडी), इंटरनेट से जुड़े चिकित्सा उपकरण, रोबोट आधारित तकनीक और दूर से जांच जैसी नई तकनीकों में भारत के पास देश और दुनिया की स्वास्थ्य जरूरतों के लिए नए समाधान विकसित करने के बड़े अवसर हैं।

जैसे-जैसे भारतीय कंपनियां दुनिया के बाजार में विस्तार कर रही हैं, गुणवत्ता भी भारत में बने चिकित्सा उपकरणों की सबसे बड़ी पहचान बनती जा रही है। सरकार नियामक व्यवस्था को मजबूत करने, मान्यता प्राप्त जांच सुविधाओं का विस्तार करने, चिकित्सा उपकरणों की प्रभावशीलता से जुड़े वैज्ञानिक प्रमाण तैयार करने और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप व्यवस्था विकसित करने पर जोर दे रही है। इससे मरीजों की सुरक्षा बढ़ेगी और वैश्विक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धा क्षमता भी मजबूत होगी।

दुनिया के स्तर पर प्रतिस्पर्धी चिकित्सा तकनीक क्षेत्र तैयार करने के लिए सरकार, उद्योग, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य सेवा देने वालों, नए उद्यमों और निवेशकों के बीच करीबी सहयोग जरूरी है। जब प्रयोगशालाओं में तैयार विचार आसानी से कारखानों तक और वहां से मरीजों तक पहुंचते हैं, तभी नए आविष्कारों को वास्तविक लाभ में बदला जा सकता है। सरकार ऐसी स्थिर और पारदर्शी नीतियां बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिनसे शोध, निवेश, तकनीकी साझेदारी और कारोबार करना आसान हो।

भारत जैसे-जैसे विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास एक-दूसरे को और मजबूत करेंगे। एक मजबूत चिकित्सा उपकरण उद्योग उच्च मूल्य वाले उत्पादन, कुशल रोजगार, निर्यात और तकनीकी क्षमता को बढ़ावा देगा। साथ ही इससे स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सस्ती, आसानी से उपलब्ध और किसी भी संकट के समय अधिक मजबूत बनेंगी।

भारत का चिकित्सा तकनीक क्षेत्र एशिया का चौथा सबसे बड़ा बाजार है और दुनिया के शीर्ष 20 बाजारों में शामिल है। फिलहाल इसका आकार 15 से 16 अरब डॉलर है और यह करीब 12 प्रतिशत की सालाना दर से बढ़ रहा है। इस वजह से यह देश के सबसे तेजी से बढ़ते विनिर्माण क्षेत्रों में से एक बन गया है।

विकसित भारत का लक्ष्य गुणवत्ता, नए आविष्कार और सभी को साथ लेकर चलने के आधार पर दुनिया में नेतृत्व करने पर जोर देता है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि नई चिकित्सा तकनीकें भारत की प्रमुख स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करें। इनमें माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य, गैर-संचारी रोग, आपातकालीन चिकित्सा, कैंसर, हृदय रोग और ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच शामिल हैं।

व्यंग्य

नौकरशाहों का शिकंजा

इसरो के पूर्व चेयरमैन जी. माधवन नायर ने अब वो राज़ बताया है, जिस पर कयास लग रहे थे। उन्होंने कहा कि इसरो में वैज्ञानिकों के ऊपर नौकरशाहों का शिकंजा कसने की प्रवृत्ति बढ़ी है।

इसी महीने यह चौंकाने वाली खबर आई कि तकरीबन 120 वैज्ञानिकों और तकनीक-कर्मियों ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) से इस्तीफा दे दिया, अथवा समय से पहले अवकाश ग्रहण कर लिया है। इनमें गगनयान, चंद्रयान-3 और स्पाडेक्स जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियानों से जुड़े वैज्ञानिक शामिल बताए गए। तब से इसरो से वैज्ञानिकों के ₹मोहभंग₹ को लेकर कई तरह के कयास लगाए जाते रहे हैं। बहरहाल, केंद्र का रुख उलटबासी की तरह रहा। वैज्ञानिकों के असंतोष के कारणों का पता लगाने का इरादा दिखाने के बजाय सरकार ने सख्ती का पैगाम दिया। अंतरिक्ष विभाग ने वैज्ञानिकों के इस्तीफे और स्वैच्छिक अवकाश-ग्रहण पर रोक लगा दी।

बहरहाल, इसरो के पूर्व चेयरमैन जी. माधवन नायर ने अब एक मीडिया इंटरव्यू में वो राज़ बताया है, जिस पर कयास लग रहे थे। उन्होंने कहा कि इसरो में 'ब्यूरोक्रेटाइजेशनÓ यानी वैज्ञानिकों के ऊपर नौकरशाहों का शिकंजा कसने की प्रवृत्ति बढ़ी है। यह वैज्ञानिकों के पलायन का प्रमुख कारण बना है। नायर ने दो टूक कहा कि वैज्ञानिक केवल पैसों के लिए इसरो छोड़ कर नहीं जा रहे, बल्कि संस्थान में बढ़ती नौकरशाही और प्रशासनिक जटिलताएं इसकी बड़ी वजह हैं। नायर ने ये सुझाव भी दिया है कि अंतरिक्ष आयोग के पूर्ण अधिकारों को बहाल किया जाए और शीर्ष प्रतिभाओं के लिए प्रदर्शन-आधारित इंसेंटिव फिर से शुरू की जाए। इन बातों का अर्थ है कि मौजूदा सरकार ने इन दोनों मामलों में पहले से जारी चलन को पलट दिया है।

नायर ने कहा कि नई संस्थाओं (जैसे इन-स्पेस और एनएसआईएल) के आने से फैसले लेने की प्रक्रिया जटिल हुई है, जिसे फिर से सरल और प्रभावी बनाने की जरूरत है। नायर ने चेतावनी दी है कि बाहरी एजेंसियों की ओर से इसरो के अत्यधिक प्रशिक्षित कर्मियों और समृद्ध संसाधनों को अपनी ओर खींचने का जबरदस्त दबाव है, जिससे अंतरिक्ष कार्यक्रम को गंभीर नुकसान पहुंचेगा। जिस समय निजी क्षेत्र ने भी भारत के अंतरिक्ष अभियान क्षेत्र में कदम रखा है, ऐसी टिप्पणियों का खास महत्त्व हो जाता है। ये टिप्पणियां सरकार की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाती हैं। क्या केंद्र इस बारे में देश को भरोसे में लेगा?

ब्लॉग

जीआई टैग: वैश्विक ब्रांडों में पारंपरिक संपदा की वृद्धि

भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग स्थानीय समुदायों के लिए आर्थिक अवसर पैदा करते हुए भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में उभरा है। उत्पादों को उनके मूल स्थान से जोड़कर, जीआई टैग पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करते हैं, दुरुपयोग को रोकते हैं और उपभोक्ता विश्वास को बढ़ाते हैं। वे कारीगरों, बुनकरों, किसानों और उत्पादक समूहों को बेहतर बाजार पहचान हासिल करने और प्रीमियम बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने में मदद करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत के जीआई इकोसिस्टम का काफी विस्तार हुआ है, जो एक मजबूत कानूनी ढांचे और बढ़ती जन जागरूकता द्वारा समर्थित है। सरकार की पहल वित्तीय सहायता, निर्यात संवर्धन, पर्यटन एकीकरण और समर्पित विपणन प्लेटफार्मों के माध्यम से इस इकोसिस्टम को और मजबूत कर रही है। साथ ही, ये प्रयास जीआई उत्पादों को ग्रामीण विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और निर्यात-आधारित विकास के वाहकों के रूप में बदल रहे हैं। बनारस में एक बुनकर एक बनारसी साड़ी बनाने में कई सप्ताह का समय लगाता है। जटिलतापूर्ण जरी के काम का हर धागा असाधारण सटीकता और कौशल के साथ बुना जाता है। ये तकनीकें रातोंरात नहीं सीखी जाती हैं। वे सदियों पुरानी परंपरा को संरक्षित करते हुए पीढ़ियों से चले आ रहे हैं।

फिर भी, इन प्रयासों और शिल्प कौशल के बावजूद, कई प्रामाणिक बनारसी साड़ियां अक्सर अपने वास्तविक मूल्य से बहुत कम कीमतों पर बेची जाती हैं। खरीदार हमेशा हाथ से बुनी हुई असली साड़ी को अन्य नकलों से अलग करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। यह वह जगह है जहां दो शब्द यानी जीआई टैग (भौगोलिक संकेत) सभी अंतर बनाते हैं।

एक जीआई टैग प्रमाणित करता है कि साड़ी वास्तव में बनारस में पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके बनाई गई है। यह खरीदारों को इसकी प्रामाणिकता, गुणवत्ता और सांस्कृतिक विरासत का आश्वासन देता है। परिणामस्वरूप, प्रामाणिक बनारसी साड़ी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में काफी अधिक कीमत प्राप्त कर सकती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुनकर को उनकी शिल्प कौशल के लिए अधिक मान्यता और बेहतर आर्थिक लाभ मिले। जीआई टैग कारीगर शिल्प के लिए प्रामाणिकता की मुहर के रूप में कार्य करता है, उन्हें नकल, दुरुपयोग और अनधिकृत व्यावसायीकरण से बचाता है। हालांकि, इसका महत्व कानूनी सुरक्षा से कहीं आगे तक फैला हुआ है। उदाहरण के लिए, चन्नापटना के खिलौनों को 2006 में जीआई मान्यता मिली। ये मान्यता सिर्फ कर्नाटक के चन्नापटना क्षेत्र में बने लकड़ी के खिलौनों पर ही लागू होती है। खिलौनों का उत्पादन क्षेत्र की विशिष्ट लाह कला का उपयोग करके किया जाना चाहिए। हालांकि यह एक सरल प्रमाणन प्रतीत हो सकता है, टैग दूरगामी लाभ प्रदान कर सकता है।

एक जीआई टैग एक लेबल से कहीं अधिक है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार, यह ग्रामीण कारीगरों की आय को 20-30 प्रतिशत तक बढ़ा सकता है!

किसी उत्पाद की उत्पत्ति और अनूठी विरासत को प्रमाणित करके, जीआई टैग खरीदारों के बीच विश्वास पैदा करते हैं और उत्पाद की बाजार अपील को बढ़ाते हैं। जैसे-जैसे उपभोक्ता तेजी से प्रामाणिकता, परंपरा और शिल्प कौशल की तलाश कर रहे हैं, जीआई मान्यता गुणवत्ता और सांस्कृतिक विशिष्टता के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में कार्य करती है। जीआई-टैग किए गए उत्पादों की बढ़ती मांग कारीगरों को अधिक दृश्यता प्राप्त करने, प्रीमियम बाजारों तक पहुंचने, उनकी सौदेबाजी की शक्ति को मजबूत करने और उनके काम से उत्पन्न मूल्य के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने में सक्षम बनाती है। मान्यता स्थायी आजीविका के अवसर पैदा करती है। वे भविष्य की पीढ़ियों के लिए भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्वदेशी शिल्प कौशल को संरक्षित करने और बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुजफ्फरनगर गुड़ के लिए जीआई टैग ने विशिष्ट गुणवत्ता और उत्पत्ति के साथ एक प्रीमियम उत्पाद के रूप में अपनी पहचान को मजबूत करने में मदद की है। इस मान्यता का लाभ उठाते हुए, बृजनंदन एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने 2025 में बांग्लादेश को 30 मीट्रिक टन गुड़ का सफलतापूर्वक निर्यात किया। जीआई प्रमाणन ने खरीदारों के विश्वास को बढ़ाया और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उत्पाद की विपणन क्षमता में सुधार किया। परिणामस्वरूप, किसान के नेतृत्व वाली कंपनी को निर्यात के अवसरों तक पहुंच प्राप्त हुई। इसने अपने 545 सदस्यों के लिए आय की संभावनाओं को बढ़ाया और स्थानीय रूप से उत्पादित गुड़ के लिए अधिक मूल्य कायम किया।
जीआई टैग का इतिहास, दर्जा और विनियमन

पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय जीआई टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला उत्पाद था, जिसमें उत्पाद और उसके लोगो दोनों को सुरक्षा प्रदान की गई थी। अन्य शुरुआती पंजीकरणों में केरल के एक पारंपरिक हस्तशिल्प अरनमुला कन्नडी और तेलंगाना के एक प्रसिद्ध वस्त्र शिल्प पोचमपल्ली इकत शामिल थे। भारतीय जीआई उत्पादों के लिए प्रमुख निर्यात स्थलों में ब्रिटेन, इटली, यूएई, बहरीन, कतर, अमेरिका, दक्षिण कोरिया शामिल हैं।

बौद्धिक संपदा के एक रूप के रूप में, जीआई को औद्योगिक संपदा के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन और बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पहलुओं पर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के समझौते (ट्रिप्स) के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। भारत में, उनके पंजीकरण और संरक्षण की देखरेख 1999 अधिनियम के तहत भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा की जाती है। भारत ने वस्तुओं का भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 और 2002 में अधिसूचित संबद्ध नियमावली के माध्यम से विशिष्ट क्षेत्रों से जुड़े उत्पादों की सुरक्षा के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित किया है। यह ढांचा 2003 में चालू हो गया और जीआई पंजीकरण 2004-05 में शुरू हुआ। वस्तुओं के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) नियमावली, 2002 को 2025 में संशोधित किया गया था।

2025 संशोधन के माध्यम से, जीआई आवेदन दाखिल करने और संबंधित प्रक्रियाओं के लिए शुल्क में 80 प्रतिशत की कमी की गई है। टैग के लिए नवीनीकरण शुल्क भी 3,000 रुपये से घटाकर केवल 500 रुपये कर दिया गया है! भारत हस्तशिल्प उत्पादों, कृषि उत्पादों, निर्मित वस्तुओं, खाद्य उत्पादों और प्राकृतिक उत्पादों जैसी श्रेणियों में जीआई-टैग वाले उत्पादों का केन्द्र है। हस्तशिल्प उत्पाद- अधिनियम के तहत 445 हस्तशिल्प उत्पाद और 27 उत्पाद लोगो (दिसंबर 2025 तक) पंजीकृत किए गए हैं। उदाहरण के तौर पर जम्मू-कश्मीर की पश्मीना, पश्चिम बंगाल की बालूचरी साड़ी और उत्तर प्रदेश की बनारस गुलाबी मीनाकारी शिल्प शामिल हैं। कृषि उत्पाद- 251 उत्पादों को पंजीकृत किया गया है, जो अनाज, फल, सब्जियां, मसाले और गैर-बासमती चावल सहित विभिन्न प्रकार की फसलों में फैले हुए हैं। विनिर्माण उत्पाद- 64 विनिर्माण उत्पादों को पंजीकृत किया गया है, जैसे नासिक वैली वाइन और कन्नौज परफ्यूम।

खाद्य उत्पाद- 66 खाद्य उत्पाद, जिनमें तैयार, पके हुए या प्रसंस्कृत व्यंजन शामिल हैं, जीआई टैग किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के बर्धमान मिहिदाना और सीताभोग, ओडिशा के केंद्रपाड़ा रसाबली और आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुपति लड्डू इसके उदाहरण हैं। प्राकृतिक उत्पाद- 5 प्राकृतिक उत्पाद- मकराना मार्बल (राजस्थान), चुनार बलुआ पत्थर (उत्तर प्रदेश), पुरुलिया के लाख (लाह) उत्पाद (पश्चिम बंगाल), पन्ना हीरा (मध्य प्रदेश) और अंबाजी सफेद संगमरमर (गुजरात) भारत में जीआई-टैग हैं। जबकि ये सख्ती से ₹प्राकृतिक₹ उत्पाद हैं, सैकड़ों अन्य प्राकृतिक मूल के सामान कृषि उत्पादों की श्रेणी में आते हैं।

भारत के कई राज्य भारत की जीआई विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। दिसंबर 2025 तक, उत्तर प्रदेश 81 जीआई-टैग उत्पादों के साथ अग्रणी राज्य है। इसके बाद तमिलनाडु (76 जीआई-टैग उत्पाद) और महाराष्ट्र (55 जीआई-टैग उत्पाद) का स्थान है। जीआई टैगः पंजीकरण, सुरक्षा और नवीनीकरण

इससे पहले कि कोई उत्पाद प्रमाणन प्राप्त कर सके, उसे विशिष्ट कानूनी और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। भारत की जीआई पंजीकरण प्रणाली परिभाषित करती है कि कौन आवेदन कर सकता है, सुरक्षा कितने समय तक चलती है, और किन परिस्थितियों में जीआई रद्द किया जा सकता है।

कानून के तहत स्थापित उत्पादकों, संगठन या प्राधिकरण का कोई भी संघ जीआई पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदक को एक कानूनी इकाई होनी चाहिए और संबंधित उत्पाद के उत्पादकों के हितों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। यदि आवेदक एक निर्माता संघ नहीं है, तो उसे यह साबित करना होगा कि यह उत्पादकों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। इसी तरह, पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले प्राधिकरण को यह भी प्रदर्शित करना होगा कि यह उत्पाद के उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करता है।

आवेदन या कोई अन्य दस्तावेज सीधे जीआई पंजीकरण में दाखिल किया जा सकता है। इसे डाक, पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या कूरियर सेवाओं द्वारा भी भेजा जा सकता है। जीआई रजिस्ट्री भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री, चेन्नई में स्थित है, जिसका अखिल भारतीय क्षेत्राधिकार है।

जीआई के तहत जिसे पंजीकृत नहीं किया जा सकता सामान्य उत्पाद नाम अब अपने मूल देश में संरक्षित नहीं हैं। ऐसे संकेत जो उपभोक्ताओं को गुमराह करते हैं या गलत तरीके से एक अलग भौगोलिक उत्पत्ति का सुझाव देते हैं। ऐसे संकेत जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं या जिनमें निंदनीय, आपत्तिजनक या अश्लील बात होती है। ऐसे संकेत जो कानूनी सुरक्षा के लिए पात्र नहीं हैं या जो लागू किसी भी कानून का उल्लंघन करते हैं। जीआई का पंजीकरण दस साल के लिए वैध है, लेकिन समय-समय पर इसका नवीनीकरण किया जा सकता है। क्या जीआई टैग रद्द किया जा सकता है? जीआई पंजीकरण का निरसन, रद्दीकरण या भिन्नता अधिनियम की धारा 27 द्वारा नियंत्रित होती है। कोई भी पीड़ित व्यक्ति पंजीकृत जीआई को रद्द करने या उसमें बदलाव करने के लिए पंजीयक या सक्षम प्राधिकारी के पास आवेदन कर सकता है। यदि आवश्यक हो तो पंजीयक या अपीलीय बोर्ड भी स्वयं इस तरह की कार्रवाई शुरू कर सकता है।

यह धोखाधड़ी या गलत बयानी के माध्यम से प्राप्त किया गया था। यह अब अपने मूल देश में संरक्षित नहीं है या अनुपयोगी हो गया है। इसके उपयोग से उपभोक्ताओं को धोखा मिलने की संभावना है, किसी भी कानून का उल्लंघन होता है, या इसमें निंदनीय या अश्लील बात होती है।

सरकार जागरूकता, बाजार पहुंच, निर्यात और कानूनी सुरक्षा में सुधार के उद्देश्य से पहल के माध्यम से जीआई उत्पादों को बढ़ावा दे रही है। आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण के अनुरूप, ये प्रयास कारीगरों, किसानों और उत्पादक समुदायों को सशक्त बना रहे हैं। वे भारत के अद्वितीय क्षेत्रीय उत्पादों की घरेलू और वैश्विक मान्यता को भी बढ़ा रहे हैं।

शिवरात्रि कल, डाक कांवड़ की बढ़ी रफ्तार, दिल्ली-दून हाईवे पर उमड़ा केसरिया सैलाब

आर्यावर्त संवाददाता

मेरठ। मंगलवार को शिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। पर्व नजदीक आने के साथ ही कांवड़ मार्ग पर शिवभक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर लौट रहे कांवड़ियों से दिल्ली-दून हाईवे और कांवड़ मार्ग पूरी तरह केसरिया रंग में रंगा नजर आ रहा है।

सुबह से देर रात तक हाईवे पर हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। पैदल कांवड़ लेकर चलने वालों में बच्चे, युवा, बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल हैं। कई महिला कांवड़िए छोटे बच्चों के साथ यात्रा करती नजर आ रही हैं। शिवभक्त लगातार हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने गांव और शहरों की ओर बढ़ रहे हैं।

हाईवे पर बढ़ने लगी डाक कांवड़

शिवरात्रि नजदीक आने के साथ ही हाईवे पर डाक कांवड़ के जत्थे भी दिखाई देने लगे हैं। आने वाले समय में इनकी संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। कांवड़ियों की सुविधा के लिए मार्ग में जगह-जगह सेवा शिविर लगाए गए हैं। इन शिविरों में भोजन, पेयजल, फल और चिकित्सा समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

कांवड़ यात्रा में दिखे अनोखे रंग

मेरठ की कांवड़ यात्रा में शिवभक्ति के साथ कई अनोखे स्वरूप भी देखने को मिल रहे हैं। मोदीपुरम और कंकरखेड़ा कांवड़ मार्ग पर रविवार को महाकाली स्वरूप की कांवड़ आकर्षण का केंद्र रही। इस कांवड़ पर नरमुंड और कंकाल लगाए गए हैं। इसके अलावा बाइक पर एके-47 का 3D डिजाइन भी राहगीरों का ध्यान खींच रहा है। लोग इन कांवड़ों की तस्वीरें लेते नजर आए।

दौराला के पास बढ़ती भीड़ के कारण सार्जन डीजे को भी हटा दिया गया। पुलिस ने इसे बैनर से सील कर सिवाया टोल प्लाजा की ओर रवाना किया। पुलिस अधीक्षक विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि व्यवस्था न बिगड़े, इसलिए डीजे को कहीं रुकने की अनुमति नहीं दी गई है। इसे बेहद कम समय के लिए संचालित करने की शर्त रखी गई है।

कांवड़ लेकर जा रहीं रूबी खान का सम्मान

बागपत रोड स्थित विवेक रिजॉर्ट में आयोजित पांचवें कांवड़ सेवा शिविर में हरिद्वार से कांवड़ लेकर पुरा महादेव जा रहीं लोनी निवासी रूबी खान का अभिनंदन किया गया। रूबी अपनी साथी मुस्कान के साथ हरिद्वार से पैदल गंगाजल लेकर पुरा महादेव जा रही हैं। यात्रा के दौरान आराम के लिए वह विवेक रिजॉर्ट स्थित शिविर में रुकी थीं। कांवड़ सेवा समिति बाफर की ओर से उनका सम्मान किया गया। शिविर संयोजक विवेक बाफर ने कहा कि रूबी खान की कांवड़ यात्रा गंगा-जमुनी तहजीब की अनूठी मिसाल है। रूबी खान ने कहा कि हरिद्वार से मेरठ तक यात्रा के दौरान उन्हें कहीं भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वह दूसरे समुदाय से हैं। उन्होंने हर साल कांवड़ लाने का संकल्प भी लिया है।

राज्यमंत्री ने कांवड़ियों की सेवा की

प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ. सोमेंद्र तोमर ने रविवार को कांवड़ सेवा शिविरों में पहुंचकर शिवभक्तों की सेवा की। उन्होंने कांवड़ लेकर भगवान भोलेनाथ के धाम की ओर जा रहे श्रद्धालुओं का सेवा-सत्कार किया और उन्हें प्रसाद व आवश्यक सामग्री वितरित की।

डॉ. सोमेंद्र तोमर ने कहा कि श्रावण मास में शिवभक्तों की सेवा करना सौभाग्य और पुण्य का कार्य है। उन्होंने इसे भगवान शिव की आराधना के समान बताया। इस दौरान उन्होंने भगवान भोलेनाथ से शिवभक्तों, उनके परिवारों और प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना की।

चुनौतियों से न घबरायें, साहस से करें सामना : कर्नल

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के दत्तोपंत ठेंगड़ी विधि संस्थान द्वारा सोमवार को आर्यभट्ट सभागार में छात्र-छात्राओं के लिए "चुनौतियों से कैसे लड़ा जाए" विषय पर प्रेरणादायी मोटिवेशनल टॉक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता कीर्ति चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल पुष्पेंद्र सिंह रहे। मुख्य वक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल पुष्पेंद्र सिंह, कीर्ति चक्र ने कहा कि जीवन में चुनौतियां प्रत्येक व्यक्ति के सामने आती हैं, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, अनुशासन और आत्मविश्वास बनाए रखते हैं। उन्होंने अपने सैन्य जीवन के अनुभव साझा करते हुए विद्यार्थियों का आह्वान किया कि वे कठिनाइयों से घबराएं नहीं और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहें। उन्होंने विद्यार्थियों को नेतृत्व की भावना विकसित करने की प्रेरणा देते हुए कहा कि नेतृत्व केवल आदेश देने का नाम नहीं है, बल्कि कठिन समय में स्वयं आगे बढ़कर उदाहरण प्रस्तुत करने का नाम है। उन्होंने कहा कि युवाओं को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हुए राष्ट्र और समाज के प्रति अपने दायित्वों का भी निर्वहन करना चाहिए।कुलपति प्रो. वंदना सिंह ने कहा कि लेफ्टिनेंट कर्नल पुष्पेंद्र सिंह, कीर्ति चक्र का जीवन युवा पीढ़ी के लिए साहस, कर्तव्यनिष्ठा, राष्ट्रभक्ति और अनुशासन की प्रेरणादायी पाठशाला है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को शैक्षणिक ज्ञान के साथ-साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने का साहस, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता भी विकसित करनी चाहिए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मुख्य वक्ता के सैन्य अनुभव और जीवन-संघर्ष विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण में मार्गदर्शक सिद्ध होंगे।

फर्जी डिग्री से बन गए वकील, प्रयागराज में 12 पर एफआईआर

आर्यावर्त संवाददाता

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्ती के बाद फर्जी शैक्षिक डिग्री के आधार पर वकालत करने के आरोप में 12 अधिवक्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। अलग-अलग विश्वविद्यालयों से कथित तौर पर फर्जी डिग्री हासिल कर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में पंजीकरण कराने के मामले में पुलिस ने इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

प्रयागराज के सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। मामला बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सचिव आरके शुक्ला की तहरीर पर दर्ज किया गया है। आरोप है कि संबंधित अधिवक्ताओं ने अलग-अलग विश्वविद्यालयों की डिग्रियों के आधार पर बार काउंसिल में पंजीकरण कराया, लेकिन सत्यापन के दौरान उनकी डिग्रियां कथित रूप से फर्जी पाई गईं। मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचने के बाद कोर्ट ने फर्जी डिग्री के आधार पर अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण के मामलों को गंभीरता से लिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक, 3 जून 2026 को हाईकोर्ट की ओर से इस संबंध में आदेश दिया गया था, जिसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ी। बार काउंसिल की ओर से की गई शिकायत पर पुलिस ने 12 अधिवक्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अब विवेचना में उनकी डिग्रियों, विश्वविद्यालयों से जारी प्रमाणपत्रों और बार काउंसिल में पंजीकरण के दौरान जमा किए गए दस्तावेजों की जांच की जाएगी।

कई जिलों से जुड़े हैं आरोपी

एफआईआर में शामिल अधिवक्ताओं का संबंध लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, मथुरा, गौतमबुद्धनगर, हरदोई, सहारनपुर, गाजियाबाद और प्रतापगढ़ समेत कई जिलों से बताया गया है। एफआईआर में शामिल नामों में सुनील कुमार अवस्थी, नफीजुल हसन सिद्दीकी, शोभित कुमार यादव, पंकज कुमार, जय नारायण कटियार, नफीस अहमद, देवेश कुमार, श्याम सिंघल, पवन हिंदोल, दीपक कश्यप, अभय सर्वसेना और सत्यम मिश्रा शामिल हैं।

दो राजनीतिक चेहरों के नाम भी चर्चा में

मामले में शामिल श्याम सिंघल को पवन हिंदोल का संबंध भाजपा से है। हालांकि, इन सभी मामलों में आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही होगी। पुलिस की विवेचना में यह पता लगाया जाएगा कि संबंधित डिग्रियां किन विश्वविद्यालयों से जारी हुईं? उनकी वास्तविकता क्या है और बार काउंसिल में पंजीकरण के समय उनका सत्यापन किस स्तर पर हुआ? इसके साथ ही यह भी जांच का विषय होगा कि यदि दस्तावेज फर्जी थे तो उनके आधार पर अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण कैसे हुआ?

दारुल उलूम में कल जल चढ़ाने का एलान, पुलिस और प्रशासन सतर्क, माहौल खराब करने वालों को दी चेतावनी

आर्यावर्त संवाददाता

देवबंद/सहारनपुर। हिंदू रक्षा दल के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा ने 11 अगस्त को दारुल उलूम में जल चढ़ाने का एलान किया है। इसके बाद से पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। वहीं, अपने विवादित बयानों और प्रदर्शनों को लेकर ललित शर्मा पहले भी चर्चाओं में रहे हैं। विवादित बयान की वजह से उन पर उत्तराखंड में प्राथमिकी तक दर्ज हो चुकी है।

बता दें कि ललित शर्मा ने आठ अगस्त को सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके कहा कि वह 11 अगस्त को दारुल उलूम पहुंचकर जल चढ़ाएंगे। उनका दावा है कि दारुल उलूम परिसर में करीब 14 फीट नीचे शिव मंदिर और शिवलिंग मौजूद हैं। मई में भी ऐसा दावा करते हुए उन्होंने प्रशासन से वैज्ञानिक जांच और खोदाई कराने की मांग की थी।

प्रशासन की ओर से उनके दावे की जांच के संबंध में प्रक्रिया की बात कही गई थी। जून में देहरादून के सहसपुर क्षेत्र के बैरागीवाला गांव में सिंचाई के पानी को लेकर हुए विवाद में भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला मीडिया प्रभारी विनोद कुमार की मौत के बाद ललित शर्मा पर कथित भड़काऊ और सांप्रदायिक टिप्पणी करने का आरोप लगा था। इस मामले में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी।

जून में शामली के एक कथित धर्मांतरण प्रकरण को लेकर उन्होंने प्रदर्शन और आत्मदाह की घोषणा की थी। बाद में उनके नेतृत्व में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने शामली रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया था। दिल्ली के उत्तम नगर में युवक तरुण की हत्या के बाद मार्च में भी उनके नाम से कथित तौर पर ईद के दौरान खून की होली खेलने जैसी चेतावनी सामने आई थी। इसके अलावा भी ललित शर्मा कई मामलों में सुर्खियों में रह चुके हैं।

> किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। माहौल खराब करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा।
> \- अमित कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी, देवबंद।

दारुल उलूम की चुप्पी, पुलिस प्रशासन मुस्तैद

जल चढ़ाने की चेतावनी के मामले में दारुल उलूम ने कुछ भी कहने से मना कर दिया, लेकिन पुलिस प्रशासन सतर्क है। हालांकि कांवड़ यात्रा के चलते जगह-जगह पुलिस बल की तैनाती है। वहीं, खुफिया विभाग के अधिकारी भी ललित शर्मा की चेतावनी के बाद सक्रिय हो गए हैं।

विवादित बयानों को लेकर पहले भी सुर्खियों में रहे हैं ललित शर्मा

दारुल उलूम में 11 अगस्त को जल चढ़ाने का एलान कर सुर्खियों में आए हिंदू रक्षा दल के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा पहले भी विवादित बयानों और प्रदर्शनों को लेकर चर्चाओं में रहे हैं। उनके बयानों को लेकर उत्तराखंड में प्राथमिकी तक दर्ज हो चुकी हैं।

संयुक्त किसान मोर्चा ने किया विरोध प्रदर्शन

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। कलेक्ट्रेट परिसर में सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन भारत छोड़ो दिवस की 84वीं वर्षगांठ के अवसर पर जेल भरोश कार्यक्रम के तहत आयोजित किया गया था। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। केंद्र सरकार द्वारा 9 दिसंबर 2021 को दिल्ली की सीमाओं पर हुए किसान संघर्ष के बाद दिए गए लिखित आश्वासनों को लागू न किए जाने पर गहरा रोष व्यक्त किया। इन आश्वासनों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (डैच) की गारंटी, ऋण माफी, बिजली के निजीकरण को रोकना और किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेना शामिल था। प्रदर्शन के दौरान, ै ज्ञड ने अपनी प्रमुख मांगों का एक मांग पत्र प्रस्तुत किया। इसमें सभी फसलों के लिए ब250ः न्यूनतम समर्थन मूल्य (डैच) की कानूनी गारंटी और सुनिश्चित सरकारी खरीद का प्रावधान शामिल है। संगठन ने ग्रामीण ऋणग्रस्तता को समाप्त करने, किसानों और दिहाड़ी मजदूरों की आत्महत्याओं को रोकने के लिए व्यापक ऋण माफी लागू करने की भी मांग की। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक किसान आत्महत्या पीड़ति परिवार को ₹25 लाख का मुआवजा देने की मांग की गई।श्रमिकों के हितों से संबंधित मांगों में चारों श्रम संहिताओं को रद्द करना और सभी श्रमिकों के लिए ₹42,000 प्रति माह का वैधानिक न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करना शामिल है। मनरेगा (डळछत्म्ळ।) को बहाल और मजबूत करने के साथ-साथ प्रति वर्ष 200 दिनों के रोजगार की गारंटी और न्यूनतम ₹700 प्रति दिन की मजदूरी सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है।

स्कूल के पास लगा कचरों का अम्बार

जौनपुर। जहां एक तरफ सरकार के द्वारा चलाया जा रहा स्वच्छता अभियान को नगर पंचायत कजगांव मुँह चिढ़ा रहा है । नगर पंचायत कार्यालय के ठीक बगल में स्थित प्राथमिक विद्यालय के अगल-बगल कचरों का अम्बार लगा हुआ है जिसके चलते आस-पास पूरी तरह से नरकीय बना हुआ है जहां एक तरफ उक्त नगर पंचायत में साफ-सफाई करने के लिए दर्जनों से अधिक सफाई कर्मचारियों को नियुक्ति कि गयी है वहीं दूसरी तरफ सफाई कर्मी के द्वारा साफ-सफाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है।ऐसी स्थिति में देखा जाए तो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा स्वच्छता अभियान उक्त नगर पंचायत में पूरी तरह से वहाँ विफल देखने को मिल रहा है। देश के भविष्य कहे जाने वाले नौनिहाल जब विद्यालय पढ़ने आते हैं तो अगल-बगल लगी गन्दगी से विद्यालय के बच्चे भी परेशान रहते हैं।

लखीमपुर खीरी में कांवड़ियों पर पथराव, एक युवक का सिर फूटा, पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में लिया

आर्यावर्त संवाददाता

लखीमपुर खीरी। लखीमपुर के खीरी थाना क्षेत्र में रविवार देर रात कांवड़ियों के जत्थे पर अराजकतत्वों ने पथराव कर दिया। इससे सड़क पर अफरा तफरी मच गई। पथराव के दौरान एक कांवड़िया घायल हो गया। उसका सिर फूट गया। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। पुलिस ने आठ-नौ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस ने प्रेसनोट जारी करते हुए बताया कि घटना एक मानसिक रूप से बीमार किशोर ने अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक गांव रुखिया से करीब 40-50 कांवड़िये रविवार रात नहर के पास स्थित माता मंदिर से जल भरकर लिलौटी नाथ मंदिर जलाभिषेक करने जा रहे थे। जैसे ही कांवड़ियों का जत्था जुलाहनपुरवा के पास पहुंचा। इसी दौरान अराजकतत्वों ने जत्थे पर पथराव शुरू कर दिया। अचानक हुए पथराव से कांवड़ियों में भगदड़ मच गई।

पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में लिया

बताया जा रहा है कि पथराव में राजापुर निवासी कांवड़िया विकास के सिर में चोट लग गई। किसी ने घटना की सूचना पुलिस को दी तो कुछ ही देर में सीओ विवेक तिवारी और सदर कोतवाल राजेश कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने मामले में आठ-नौ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

एसपी डॉ. ख्याति गर्ग ने बताया कि पथराव की सूचना पर पुलिस पहुंची थी। प्रथम दृष्टया घटना एक मानसिक रूप से बीमार नाबालिग लड़के द्वारा की गई। फिर भी पुलिस अन्य बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है।

संक्षेप

वनरक्षक की संदिग्ध परिस्थितियों में में मौत

जौनपुर। बरसठी थाना क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान एक वनरक्षक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गयी। सोमवार को बनकट कछोटा के पास सड़क किनारे वनरक्षक 34 वर्षीय रवि यादव खून से लथपथ हालत में मिले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।बताया जा रहा है कि रवि यादव बाइक से अपने क्षेत्र में भ्रमण के लिए निकले थे। इसी दौरान वह सड़क किनारे गंभीर हालत में मिले। उनके शरीर पर चोट और खून के निशान पाए जाने से घटना को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रथम दृष्टया मामला सड़क हादसे से जुड़ा हो सकता है, हालांकि मौत की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं है।पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस हादसे समेत अन्य संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वनरक्षक की मौत की सही वजह स्पष्ट हो सकेगी। घटना के बाद वन विभाग और मृतक के परिजनों में भी शोक का माहौल है।

क्रॉस कंट्री रेस में दिखेगा खिलाड़ियों का दम

जौनपुर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर खेल विभाग की ओर से जिले में क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन किया जाएगा। जिला खेल कार्यालय के तत्वावधान में 15 अगस्त को इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम, सिद्दीकपुर में पुरुष एवं महिला वर्ग की क्रॉस कंट्री रेस आयोजित होगी। प्रतियोगिता का शुभारंभ सुबह 7 बजे से होगा। खेल अधिकारी के अनुसार, पुरुष वर्ग के लिए 5 किलोमीटर तथा महिला वर्ग के लिए 3 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री रेस निर्धारित की गई है। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के इच्छुक खिलाड़ी 14 अगस्त तक स्टेडियम में पूर्व चैम्पियन एथलीट कृष्ण कुमार यादव से संपर्क कर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। दूर-दराज क्षेत्रों से आने वाले खिलाड़ी 15 अगस्त को सुबह 6 बजे स्टेडियम पहुंचकर अपना नाम और पता दर्ज कराते हुए मौके पर पंजीकरण करा सकेंगे। प्रतिभागियों के लिए प्रविष्टि का अंतिम समय सुबह 6रू30 बजे निर्धारित किया गया है। इसके बाद किसी भी खिलाड़ी की प्रविष्टि स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रतियोगिता में पुरुष एवं महिला वर्ग में प्रथम छह स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को खेल विभाग की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा।

सपा ने मनाई फूलन देवी की जयंती

जौनपुर। समाजवादी पार्टी की ओर से सोमवार को पूर्व सांसद एवं वीरांगना फूलन देवी की जयंती जिला कार्यालय सदर चुंगी, अल्फस्टीनगंज में समारोहपूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता सपा जिलाध्यक्ष राकेश मौर्य ने की। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फूलन देवी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।इसके बाद आयोजित गोष्ठी में जिलाध्यक्ष ने कहा कि फूलन देवी सामाजिक विषमता के खिलाफ संघर्ष करने वाली महिला थीं। उन्होंने वंचित और शोषित समाज की आवाज को मजबूती प्रदान करने का काम किया। उनका संघर्ष महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना जाता है।गोष्ठी का संचालन जिला महासचिव आरिफ हबीब ने किया।

गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार

जौनपुर । थाना बदलापुर पुलिस ने गांजा तस्करी में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 1.850 किलोग्राम गांजा, एक मोटरसाइकिल और छोटा इलेक्ट्रॉनिक कांटा बरामद किया है। पुलिस के पुलिस टीम सरोखनपुर गांव स्थित अंडरपास पुल के पास संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान सरोखनपुर निवासी मो. हारुन को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया। तलाशी के दौरान उसके पास से 1.800 किलोग्राम गांजा तथा प्लास्टिक में रखी 20 पुड़ियों में 50 ग्राम गांजा बरामद हुआ। कुल बरामद गांजे का वजन 1.850 किलोग्राम बताया गया है। पुलिस ने मौके से हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल इलेक्ट्रॉनिक कांटा, क्विक फिक्स गम और पुराने अखबार भी बरामद किए।

फिर सुलगा नेपाल में हिंदू राष्ट्र का मुद्दा, पहाड़ से मधेश तक गूंजी मांग, सुनसरी हिंसा की भी जांच तेज

आर्यावर्त संवाददाता

बहराइच। नेपाल में करीब 18 साल बाद हिंदू राष्ट्र का मुद्दा एक बार फिर सड़क से सियासत के केंद्र तक पहुंच गया है। सुनसरी के देवानगंज में धार्मिक विवाद के बाद भड़के तनाव ने इसे नई धार दी है। काठमांडू से लेकर तराई और सीमावर्ती इलाकों तक हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है। अब इसे केवल धार्मिक मांग नहीं, बल्कि नेपाल की सांस्कृतिक पहचान, परंपरा और ऐतिहासिक विरासत से भी जोड़कर देखा जा रहा है।

राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी (आरपीपी) लंबे समय से नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने और राजशाही बहाल करने की समर्थक रही है। मई 2026 में पार्टी की मुख्य सचेतक खुशबू ओली ने संसद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया में सनातन हिंदू राष्ट्र और संवैधानिक राजशाही समेत अन्य मुद्दों को शामिल करने की मांग की थी। मार्च 2026 के चुनाव में प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) ने 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 182 सीटें जीतीं। हालांकि हिंदू राष्ट्र की व्यवस्था बहाल करने के लिए संविधान संशोधन और व्यापक राजनीतिक सहमति जरूरी होगी।

नेपाल का विश्व हिंदू परिषद और हिंदू स्वयंसेवक संघ समेत कई संगठन भी हिंदू राष्ट्र के समर्थन में हैं। विश्व हिंदू परिषद नेपाल की मातृशक्ति विभाग की अध्यक्ष कृष्णा पांडे के अनुसार, मई 2026 में सरकार को वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र की पुनर्स्थापना समेत कई सुझाव दिए गए थे और काठमांडू में मंत्रालय स्तर पर बैठक हुई थी।

नेपाल 1768 से 2008 तक करीब 240 वर्ष हिंदू राजशाही वाला देश रहा। 2007 के अंतरिम संविधान में इसे धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया और 28 मई 2008 को राजशाही समाप्त कर गणतंत्र घोषित किया गया। नेपाल के सुनसरी जिले के कप्तानगंज में 27 जुलाई को दो समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प की जांच अब फायरिंग के तकनीकी पहलुओं तक पहुंच गई है। गृह मंत्रालय के सहसचिव भूपेंद्र थापा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति ने घटनास्थल और घायलों से जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। समिति हिंसा की वजह, सुरक्षा बलों की कार्रवाई और प्रशासनिक चूक के साथ गोली चलने की परिस्थितियों की भी जांच करेगी।

गोलीबारी के बैलिस्टिक और फोरेंसिक साक्ष्यों की पड़ताल के लिए पुलिस निरीक्षक दीपेश अवस्थी और पुलिस उपनिरीक्षक मोहनसिंह धामी को विशेषज्ञ के तौर पर समिति में शामिल किया गया है। जांच का अहम बिंदु यह है कि सुरक्षा बलों की फायरिंग निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप थी या नहीं। हिंसा में 24 वर्षीय ओमप्रकाश मेहता की मौत हुई थी, जबकि नौ नागरिकों समेत कई लोग घायल हुए थे। घटना के बाद प्रशासनिक बदलाव करते हुए ईश्वरी प्रसाद अर्याल को प्रमुख जिला अधिकारी बनाया गया है। नेपाल पुलिस, सशस्त्र पुलिस, नेपाली सेना और राष्ट्रीय जांच विभाग की निगरानी बढ़ाई गई है।

मानवाधिकार आयोग भी कर रहा मामले की जांच

उधर, सिरहा के गोलबजार में 30 जुलाई को प्रदर्शन के दौरान 15 वर्षीय गणेश यादव की मौत की अलग जांच चल रही है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भी सुनसरी मामले की जांच शुरू कर दी है। आयोग की टीम ने प्रशासन, पुलिस, अस्पताल और प्रभावित पक्षों से घटना की जानकारी जुटाई है। सरकार ने संवेदनशील जिलों में सुरक्षा के साथ संवाद और सामाजिक सद्भाव बढ़ाने पर जोर दिया है। उधर कप्तानगंज में स्थिति अब धीरे-धीरे सामान्य होने की ओर है। राजमार्ग क्षेत्र से कर्फ्यू हटाया जा चुका है, हालांकि संवेदनशील इलाकों में निगरानी जारी है।

कुछ लोगों को क्यों होता है बार-बार यूरिन इंफेक्शन? कहीं ये किसी बड़ी बीमारी का संकेत तो नहीं

यदि बार-बार यूटीआई हो रहा है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि बार-बार संक्रमण किडनी तक भी पहुंच सकता है और गंभीर जटिलताएं पैदा कर सकता है। पेशाब करते समय जलन, बार-बार पेशाब आने की इच्छा या पेट के निचले हिस्से में दर्द ये सभी यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन (यूटीआई) के सामान्य लक्षण हैं।

क्या आपको भी अक्सर पेशाब करते समय जलन होती है, बार-बार पेशाब की इच्छा होती है और पेट के निचले हिस्से में दर्द बना रहता है? अगर हां तो सावधान हो जाइए ये सभी यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन (यूटीआई) के लक्षण हो सकते हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि अधिकतर लोगों को जीवन में कभी न कभी यूटीआई हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों में यह समस्या बार-बार लौट आती है।

यूटीआई को आमतौर पर महिलाओं की समस्या माना जाता है, जबकि ये पुरुषों को भी हो सकती है। डॉक्टर कहते हैं, किसी व्यक्ति को छह महीने में दो या उससे अधिक बार यूटीआई हो, तो इसे बार-बार होने वाला यूटीआई माना जाता है। महिलाओं में यह समस्या पुरुषों की तुलना में अधिक होती है क्योंकि उनकी मूत्रमार्ग छोटी होती है। इससे बैक्टीरिया आसानी से मूत्राशय तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा बुजुर्गों, डायबिटीज के मरीजों और गर्भवती महिलाओं में भी इसका जोखिम बढ़ जाता है।

सबसे पहले जानिए यूटीआई होती क्यों है?

डॉक्टर बताते हैं, यूटीआई होने का सबसे आम कारण ई. कोलाई बैक्टीरिया का संक्रमण है, जो सामान्य रूप से आंत में पाया जाता है। जब यह मूत्र मार्ग में पहुंच जाता है तो संक्रमण पैदा कर सकता है। लगभग 80-90 प्रतिशत यूटीआई के मामले इसी बैक्टीरिया के कारण होते हैं। यदि बार-बार यूटीआई हो रहा है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि बार-बार संक्रमण किडनी तक भी पहुंच सकता है और गंभीर जटिलताएं पैदा कर सकता है। आइए समझ लेते हैं कि कुछ लोगों को बार-बार ये दिक्कत क्यों होती है?

कहीं कम पानी तो नहीं है इसका कारण?

जो लोग पूरे दिन बहुत कम पानी पीते हैं या लंबे समय तक पेशाब रोककर रखते हैं, उनमें संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेने से पेशाब होता रहता है जिससे बैक्टीरिया को बाहर निकलने में मदद मिलती है।

पानी कम पीने से पेशाब कम बनता है और बैक्टीरिया लंबे समय तक मूत्राशय में बने रह सकते हैं। दिनभर में कम से कम 2-3 लीटर पानी पीते रहना आपके खतरे को कम कर सकता है।

अक्सर शुगर हाई रहना नुकसानदायक

डायबिटीज की स्थिति में खून और पेशाब दोनों में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। अधिक ग्लूकोज बैक्टीरिया की वृद्धि को बढ़ावा दे सकता है।

इसके अलावा डायबिटीज के कारण शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली भी कमजोर हो जाती जिससे संक्रमण से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है।

यही वजह है कि बार-बार यूटीआई होने वाले मरीजों में ब्लड शुगर की जांच महत्वपूर्ण मानी जाती है।

इन कारणों को भी जानिए

महिलाओं में जननांगों की साफ-सफाई में कमी भी बैक्टीरिया को मूत्रमार्ग तक पहुंचा सकती है। साफ अंडरगारमेंट न पहनना और लंबे समय तक गीले कपड़े पहनना संक्रमण के जोखिम को बढ़ाने वाला हो

सकता है।

बढ़ा हुआ प्रोस्टेट, किडनी स्टोन, न्यूरोलॉजिकल रोग या मूत्राशय की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। इसके कारण भी कई लोगों में बार-बार यूटीआई होने का खतरा रहता है।

रजोनिवृत्ति के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन कम होने से योनि और मूत्रमार्ग की प्राकृतिक सुरक्षा कमजोर हो सकती है, जिससे यूटीआई का खतरा बढ़ता है।

कुछ महिलाओं में यौन संबंध के बाद भी बैक्टीरिया मूत्रमार्ग में पहुंच सकते हैं।

लंच बॉक्स को अधिक पौष्टिक बनाने के लिए अपनाएं ये 5 सरल तरीके

लंच बॉक्स में खाने की तैयारी करना एक कला है, जो आपके दिनभर की ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करता है। सही पोषण आपको शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। इस लेख में हम आपको कुछ सरल सुझाव देंगे, जिनसे आप अपने लंच बॉक्स को अधिक पौष्टिक और संतुलित बना सकते हैं, जिससे आपका दिन बेहतर हो सके।

सब्जियों का उपयोग बढ़ाएं

सब्जियां आपके लंच बॉक्स का अहम हिस्सा होनी चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, और बथुआ विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होती हैं। इनमें फाइबर भी होता है जो पाचन को बेहतर बनाता है।

इन्हें अपने लंच बॉक्स में शामिल करने से आपकी ऊर्जा स्तर भी बढ़ता है और आपको थकान महसूस नहीं होती।

सब्जियों को हल्का सा भूनकर या भाप में पकाकर खाने से उनका स्वाद बढ़ जाता है और पोषक तत्व भी सुरक्षित रहते हैं।

प्रोटीन का ध्यान रखें

प्रोटीन आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी होती है क्योंकि यह मांसपेशियों को मजबूत बनाती है और शरीर को ऊर्जा देती है।

इसके लिए आप अपने लंच बॉक्स में दाल, चना, राजमा या छोले जैसी चीजें शामिल कर सकते हैं। इनका सेवन करने से आपको भरपूर प्रोटीन मिलती है और यह आपके शरीर को ताकत देती है।

प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन दिनभर की थकान को दूर करता है और आपको तरोताजा महसूस करवाता है।

फलों को शामिल करें

फल विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं।

साथ ही ये आपकी त्वचा के लिए भी फायदेमंद होते हैं। अपने लंच बॉक्स में एक या दो फल जैसे सेब, केला या संतरा जरूर रखें।

इनका सेवन करने से आपको ताजगी महसूस होगी और आप पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करेंगे। फलों का सेवन न केवल आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि यह आपको मानसिक रूप से भी तरोताजा रखता है।

पानी पीते रहें

पानी शरीर के लिए बेहद जरूरी होता है। दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीना चाहिए ताकि शरीर में पानी की कमी न हो।

अगर आप ऑफिस या कॉलेज जाते हैं तो एक छोटी बोतल में पानी भरकर ले जाएं और समय-समय पर उसे पूरा करें। इससे आपका पाचन ठीक रहेगा और शरीर में हानिकारक तत्व भी बाहर निकलेंगे।

पानी पीने से आपको थकान महसूस नहीं होगी और आप तरोताजा महसूस करेंगे।

स्नैक्स पर ध्यान दें

स्नैक्स भी लंच बॉक्स का अहम हिस्सा होते हैं। चिप्स या बिस्किट खाने की बजाय नट्स, मखाना या भुने चने जैसे सेहतमंद विकल्प चुनें।

ये स्नैक्स न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि आपके शरीर को जरूरी पोषण भी देते हैं। इनसे आपको ऊर्जा मिलती रहती है और आप पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करते हैं।

इन सरल सुझावों को अपनाकर आप अपने लंच बॉक्स को पौष्टिक बना सकते हैं, जिससे आपका दिन बेहतर गुजर सकेगा।

महिलाओं को फिर से पसंद आने लगे हैं बड़े बैग, जानिए इनके बढ़ते चलन के कारण

बड़े बैग का चलन एक बार फिर से लौट आया है, जो सोशल मीडिया की वजह से और बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ समय से महिलाओं ने छोटे बैग को ज्यादा प्राथमिकता दी थी, लेकिन अब बड़े बैग फिर से फैशन का हिस्सा बन रहे हैं। यह बदलाव कई कारणों से हुआ है। इस लेख में हम जानेंगे कि बड़े बैग क्यों वापस फैशन में आ रहे हैं और ये कैसे महिलाओं की जीवनशैली में सहायक साबित हैं।

ज्यादा सामान रखने की सुविधा

बड़े बैग में अधिक सामान रखा जा सकता है, जिससे महिलाएं अपनी जरूरत की सभी चीजें एक साथ लेकर चल सकती हैं।

चाहे वह ऑफिस का सामान हो, बच्चों का स्कूल का सामान हो या खरीदारी का सामान, बड़े बैग में सब कुछ समा जाता है।

इससे महिलाओं को बार-बार बैग बदलने की जरूरत नहीं पड़ती और उनका समय भी बचता है। इसमें वे लैपटॉप आदि भी ले जा सकती हैं।

आरामदायक होते हैं बड़े बैग

बड़े बैग आमतौर पर ज्यादा आरामदायक होते हैं, क्योंकि इनमें मजबूत पकड़ वाले हैंडल होते हैं, जो वजन उठाने में मदद करते हैं।

इसके अलावा इनका डिजाइन भी ऐसा होता है कि वजन समान रूप से बंट जाता है, जिससे कंधे और पीठ पर कम दबाव पड़ता है।

इससे लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर भी कोई परेशानी नहीं होती और महिलाएं आसानी से अपने सामान को ले जा सकती हैं।

फैशन में भी हैं बड़े बैग

आजकल बाजार में कई तरह के डिजाइन और रंगों में बड़े बैग उपलब्ध हैं, जो हर महिला की पसंद के अनुसार होते हैं। कोई साधारण काला बैग पसंद करता है तो कोई चमकीला रंग वाला।

इसके अलावा कई बैग पर कढ़ाई या छपाई भी मिलती है, जो उन्हें और भी आकर्षक बनाते हैं। इस प्रकार बड़े बैग न केवल उपयोगी होते हैं, बल्कि स्टाइलिश भी होते हैं, जिससे वे फैशन का हिस्सा बन जाते हैं।

कई कामों के लिए उपयोगी

बड़े बैग कई प्रकार के कामों के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। इन्हें आप पिकनिक पर ले जा सकते हैं, खरीदारी करते समय इस्तेमाल कर सकते हैं या यात्रा के दौरान भी साथ रख सकते हैं।

इस प्रकार ये बैग आपकी हर जरूरत पूरी करते हैं और आपको अलग-अलग बैग खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

इससे पैसे भी बचते हैं और सामान व्यवस्थित रहता है, जिससे बाद में आसानी होती है।

पर्यावरण के अनुकूल

आजकल कई महिलाएं पर्यावरण के प्रति जागरूक हो रही हैं और प्लास्टिक बैग का उपयोग कम करना चाहती हैं।

बड़े कपड़े या जूट से बने बैग एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि ये बार-बार उपयोग किए जा सकते हैं और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते।

इस प्रकार बड़े बैग कई कारणों से महिलाओं के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं। ये न केवल सुविधाजनक होते हैं, बल्कि स्टाइलिश भी होते हैं, जिससे महिलाएं इन्हें पसंद कर रही हैं।

ई20 पेट्रोल की गुणवत्ता पर उठे सवालों पर तेल कंपनियों ने क्या कहा? जांच में मिला हर सवाल का जवाब

हाल ही में ई20 पेट्रोल (इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) में नमी और क्लोराइड होने की मीडिया रिपोर्टों के बाद तेल विपणन कंपनियों ने देशभर में इसकी सप्लाई चेन के हर स्तर पर गहन जांच कराई। जानें क्या परिणाम सामने आए हैं।

देश की सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने शुक्रवार को ई20 पेट्रोल की गुणवत्ता को लेकर उठी चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि देश भर में की गई व्यापक जांच में ईंधन में नमी या क्लोराइड सम्मिश्रण का कोई प्रमाण नहीं मिला है। कंपनियों ने स्पष्ट किया कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीएमएस) यानी ई20 की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के भीतर है और उपभोक्ताओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है।

ईंधन के दूषित होने का प्रमाण नहीं मिले

तेल कंपनियों ने एक साझा बयान में कहा कि हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्टों में ई20 पेट्रोल में नमी और क्लोराइड की मात्रा को लेकर सवाल उठाए गए थे। इसके बाद पूरे आपूर्ति तंत्र (सप्लाई चेन) में अतिरिक्त और गहन परीक्षण अभियान चलाया गया। जांच के नतीजों में कहीं भी ईंधन के दूषित होने का प्रमाण नहीं मिला और सभी नमूने निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पाए गए।

कंपनियों ने कहा कि ईंधन की गुणवत्ता उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है। अगर किसी ऐसी समस्या की आशंका होती है जो वाहनों के प्रदर्शन या उपभोक्ताओं के भरोसे को प्रभावित कर सकती है, तो उसकी वैज्ञानिक तरीके से जांच की जाती है और आवश्यक सुधारात्मक कदम तुरंत उठाए जाते हैं।

क्लोराइड की मात्रा को लेकर उठ रहे थे सवाल

कंपनियों के अनुसार, सरकार ने पेट्रोल में मिलाए जाने वाले इथेनॉल के लिए क्लोराइड की मात्रा को लेकर कड़े मानक निर्धारित किए हैं। इनका पालन सुनिश्चित करने के लिए पूरी आपूर्ति श्रृंखला में उच्च स्तर की निगरानी व्यवस्था लागू की गई है। कंपनियों ने आगे बताया कि क्लोराइड का परीक्षण देश भर में विभिन्न स्तरों पर किया जाता है, जिसमें रिफाइनरी, डिस्टिलरी, डिपो, टर्मिनल और पेट्रोल पंप शामिल हैं। इस बहुस्तरीय निगरानी व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ईंधन की गुणवत्ता हर स्तर पर तय मानकों के अनुरूप बनी रहे।

इसके अलावा ईंधन की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए सभी पेट्रोल पंपों पर प्रतिदिन 8 से 12 बार पानी की मिलावट और घनत्व की जांच की जाती है। कई स्थानों पर मोबाइल फ्यूल क्वालिटी टेस्टिंग लैब भी तैनात की गई हैं। साथ ही ईंधन के नमूनों की स्वतंत्र परीक्षण प्रयोगशालाओं में भी जांच कराई जाती है।

100 से अधिक अतिरिक्त पेट्रोल नमूनों की जांच

तेल कंपनियों ने कहा कि सप्लाई चेन के प्रत्येक स्तर पर लागू इस मजबूत और बहुस्तरीय परीक्षण प्रणाली ने एक बार फिर साबित किया है कि भारत में ई20 पेट्रोल की गुणवत्ता सुरक्षित और निर्धारित मानकों के अनुरूप है। तेल विपणन कंपनियों ने यह भी बताया कि देशभर की रिफाइनरियों से यादृच्छिक रूप से चुने गए 100 से अधिक अतिरिक्त पेट्रोल नमूनों की क्लोराइड जांच कराई गई। परीक्षण में सभी नमूनों में क्लोराइड का स्तर 1 पार्ट पर मिलियन (पीपीएम) या उससे कम पाया गया, जो निर्धारित सीमा के भीतर है। कंपनियों के अनुसार, यह परिणाम दर्शाते हैं कि भारत की रिफाइनिंग और ईंधन वितरण प्रणाली में लागू गुणवत्ता नियंत्रण उपाय प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं और ई20 पेट्रोल की गुणवत्ता को लेकर सामने आई आशंकाओं का कोई आधार नहीं है। तेल कंपनियों ने भरोसा जताया कि इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और पर्यावरणीय लक्ष्यों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है तथा इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर लगातार सख्त निगरानी रखी जा रही है।

मौसम और युद्ध से फिर बढ़ेगी महंगाई? दुनिया में खाद्य कीमतें तीन साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचीं

खराब मौसम और खाड़ी एवं काला सागर क्षेत्र में युद्ध के बीच दुनियाभर में खाद्य वस्तुओं की कीमतें जुलाई 2026 में तीन साल से ज्यादा समय के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं। एफएओ का खाद्य मूल्य सूचकांक बढ़कर 131.1 अंक हो गया। गेहूं, वनस्पति तेल और चीनी की कीमतों में भी तेजी दर्ज हुई। क्या दुनिया फिर खाद्य महंगाई की चपेट में आ सकती है? आम आदमी की थाली पर इसका कितना असर पड़ा है? आइए, सबकुछ विस्तार से जानते हैं...

खराब मौसम और खाड़ी एवं काला सागर क्षेत्र में युद्ध ने महंगाई के मोर्चे पर दुनियाभर की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के मुताबिक, वैश्विक स्तर पर खाने-पीने की वस्तुओं की कीमतें जुलाई, 2026 में बढ़कर तीन साल से ज्यादा समय के उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं। एफएओ का खाद्य मूल्य सूचकांक बीते महीने बढ़कर औसतन 131.1 अंक पहुंच गया, जो जनवरी, 2023 के बाद सबसे ऊंचा स्तर है। जून में यह सूचकांक 130.3 अंक था।

संगठन के मुख्य अर्थशास्त्री ने कहा, दुनिया को फिर उच्च खाद्य महंगाई का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ईरान और यूक्रेन युद्ध के साथ अल-नीनो के कारण लागत बढ़ने एवं फसलों की पैदावार घटने जैसे हालात बन रहे हैं। चिंता की बात यह है कि एफएओ का अनाज मूल्य सूचकांक हर महीने 3.4 फीसदी बढ़ रहा है, जिससे खाद्य कीमतों में उछाल आया है। गेहूं में भी 5.8 फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसकी वजह काला सागर से निर्यात में रुकावट और मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में गर्मी से फसलों का नुकसान होना है, जिसने बाजार की चिंता बढ़ा दी है।

वनस्पति तेल और चीनी में भी तेजी

दुनियाभर में वनस्पति तेल और चीनी की कीमतें भी तेजी से बढ़ी हैं। एफएओ के मुताबिक, वनस्पति तेल सूचकांक जुलाई में दो फीसदी बढ़कर जून, 2022 के बाद के अपने चार साल उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है।

ईरान युद्ध और बायोडीजल की मजबूत मांग के बीच क्रूड की ऊंची कीमतों ने पाम एवं सोया तेल के दाम बढ़ाए हैं।

यूरोप-एशिया में मौसम संबंधी चिंताओं और ब्राजील में इथेनॉल की मांग बढ़ने की उम्मीदों से चीनी के दाम भी 5.6 फीसदी बढ़े हैं।

हालांकि, मांस की कीमतों में जून के रिकॉर्ड स्तर से 2.8 फीसदी की गिरावट आई है।

आम आदमी की थाली 9% तक महंगी

प्याज, खाद्य तेल और रसोई गैस की कीमतों में उछाल से आम आदमी की थाली जुलाई, 2026 में सालाना आधार पर 9 फीसदी तक महंगी हो गई। क्रिसिल इंटेलिजेंस की रोटी-राइस-रेट रिपोर्ट के मुताबिक, बीते माह शाकाहारी थाली की कीमत करीब चार फीसदी बढ़कर 29.1 रुपये पहुंच गई, जो जुलाई, 2025 में 28.1 रुपये थी। वहीं, मांसाहारी थाली के दाम भी 53.5 रुपये के मुकाबले 9 फीसदी बढ़कर 58.3 रुपये पहुंच गए।

मार्च-अप्रैल में महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश के कारण प्याज की फसल को नुकसान हुआ, जिससे इसकी कीमत सालाना आधार पर 20 फीसदी बढ़ गई। खाद्य तेल और रसोई गैस के दाम में भी क्रमशः 11 फीसदी एवं 10 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि, आलू और टमाटर की कीमतों में क्रमशः 12 फीसदी एवं दो फीसदी की गिरावट से कुछ राहत जरूरत मिली।

मांसाहारी थाली की महंगाई में चिकन की बड़ी भूमिका रही, जिसकी कीमत सालाना आधार पर 14% बढ़ी है। मांसाहारी थाली की कीमतें तय करने में चिकन की हिस्सेदारी करीब 50 फीसदी होती है।

लगातार दूसरे माह आरबीआई के लक्ष्य से अधिक रहेगी महंगाई

खाने-पीने की वस्तुओं की कीमतों में उछाल के कारण जुलाई के आंकड़ों में महंगाई और बढ़ने का अनुमान है। 40 अर्थशास्त्रियों के एक सर्वे के मुताबिक, जुलाई में खुदरा महंगाई बढ़कर 4.50 फीसदी के स्तर पर पहुंच सकती है, जो जून में 4.38 फीसदी थी। अगर ऐसा हुआ, तो खुदरा महंगाई लगातार दूसरे महीने आरबीआई के 4 फीसदी के मीडियम-टर्म लक्ष्य से ऊपर रहेगी। खुदरा महंगाई के आंकड़े 12 अगस्त को जारी होंगे।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की चीफ इकनॉमिक एडवाइजर कनिका पसरीचा ने कहा, खाने-पीने की चीजों की महंगाई बढ़ रही है, जबकि दूसरी वस्तुओं की कीमतों का दबाव कम बना हुआ है। जुलाई में मानसून की स्थिति बेहतर होने से फसलों को फायदा हुआ है।

इजराइल ने ट्रंप के गाजा प्लान को ठुकराया, नेतन्याहू बोले- इजराइली सेना नहीं हटेगी पीछे

वॉशिंगटन, एजेंसी। इजराइल ने रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा समझौते को ठुकरा दिया है। होर्मुज स्ट्रेट के प्रबंधन को लेकर ईरान और ओमान के बीच संभावित समझौते की जानकारी सामने आई है, क्योंकि तेहरान ने संकेत दिया है कि दुश्मन देशों से जुड़े जहाजों को इस अहम जलमार्ग से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस बीच, यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने देश के लाल सागर तट पर सरकार के कब्जे वाले एक बंदरगाह पर हमला किया, जिससे रणनीतिक शिपिंग मार्गों के लिए खतरे और गृहयुद्ध की वापसी की आशंका बढ़ गई है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने पड़ोसी सऊदी अरब में एक तेल सुविधा केंद्र पर हमला किया। नेतन्याहू का कहना है कि जब तक हमास हथियार नहीं छोड़ता, तब तक

गाजा से कोई वापसी नहीं होगी। इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पिछले महीने ट्रंप द्वारा गाजा के लिए घोषित समझौते को खारिज कर दिया और कहा कि इजराइली सेना तब तक कोई वापसी नहीं करेगी जब तक हमास वास्तव में हथियार नहीं छोड़ देता। नेतन्याहू ने कैबिनेट की बैठक में कहा कि इजराइल 15-सूत्रीय दस्तावेज को खारिज करता है लेकिन वाशिंगटन के साथ गाजा के लिए योजनाओं पर चर्चा जारी रखेगा। उन्होंने पिछले हफ्ते भी ऐसी ही बातें कही थीं।

ट्रंप ने कहा था कि हमास आतंकवादी समूह के हथियार छोड़ने की प्रक्रिया पूरी होने पर इजराइली सेना पीछे हट जाएगी।हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य बासेम नईम ने कहा, हम रोडमैप के प्रति प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि समूह को उम्मीद है कि मध्यस्थ और अमेरिका नेतन्याहू पर दबाव डालेंगे, जो 27 अक्टूबर को होने वाले अगले चुनावों से पहले सत्ता बनाए रखने के संघर्ष के बीच घरेलू तनाव का भी सामना कर रहे हैं। 7 अक्टूबर, 2023 को हमास के नेतृत्व में इजराइल पर हुए हमले से गाजा में युद्ध शुरू हुआ था। अभी भी एक नाजुक युद्धविराम लागू है। यमन सरकार की सहयोगी 'नेशनल रेजिस्टेंस फोर्सेज' ने बताया कि मोखा बंदरगाह पर हूती हमले में कम से कम सात लोग, चार सैनिक और तीन आम नागरिक मारे गए और 15 आम नागरिक घायल हो गए। सूचना मंत्रालय के असिस्टेंट अंडरसेक्रेटरी फ़ायेद अल-नोमान ने कहा कि विद्रोहियों ने मिसाइलें और ड्रोन दागे, जिससे बंदरगाह की इमारतों और पियर्स (घाटों) के साथ-साथ कमर्शियल सामान और खाने-पीने की चीजों को भी भारी नुकसान पहुंचा। बाद में सेना ने बताया कि मिसाइलें कई इलाकों में गिरीं, जिनमें एक टेलीविजन चैनल के पास की जगह भी शामिल है।

मोखा, यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के अधीन एक मुख्य बंदरगाह है। इसे ऐसे जहाजों को संभालने के लिए रेनोवेट किया गया है जो हूतियों के कब्जे वाले होदेइदाह बंदरगाह से नहीं गुज़रते। हूतियों ने हमले की ज़िम्मेदारी ली और कहा कि उन्होंने सैन्य बलों और गोदामों को निशाना बनाया। हूती सेना के प्रवक्ता याह्या सरी ने कहा कि उन्होंने सऊदी ड्रोन द्वारा हज्जा और सादा प्रांतों के ऊपर यमन के एयरस्पेस का उल्लंघन करने के जवाब में सऊदी शहर जाजान में अरामको रिफाइनरी को भी ड्रोन से निशाना बनाया।

सऊदी ऊर्जा मंत्रालय ने बताया कि अरामको रिफाइनरी की एक फैसिलिटी में आग लग गई, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। मंत्रालय ने आग लगने की वजह नहीं बताई। इन हमलों से 2022 में हुए समझौते के बाद यमन में गृहयुद्ध के फिर से भड़कने का खतरा पैदा हो गया है।

ईरान और ओमान के बीच संभावित समझौता

ईरान और ओमान, जो होर्मुज स्ट्रेट के दोनों ओर स्थित हैं, एक अस्थायी समझौते को अंतिम रूप देने पर काम कर रहे हैं। इस समझौते से जलमार्ग फिर से खुल जाएगा, जिसमें जहाज ईरान के पास से प्रवेश करेंगे और ओमान के पास से बाहर निकलेंगे। बातचीत से जुड़े दो लोगों ने नाम न बताने की शर्त पर यह जानकारी दी, क्योंकि उन्हें सार्वजनिक रूप से बोलने की अनुमति नहीं थी। इस अंतरिम अवधि के दौरान जहाज बिना किसी शुल्क या टोल का भुगतान किए आवाजाही कर सकेंगे। इस समझौते का मकसद अमेरिका और ईरान के बीच हुए अलग अंतरिम समझौते को फिर से बहाल करना है। तेल और प्राकृतिक गैस की वैश्विक आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण इस स्ट्रेट को युद्ध से पहले एक अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग माना जाता था।

उन दो लोगों ने बताया कि इस समझौते को खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के सदस्यों का समर्थन प्राप्त है और उम्मीद है कि ईरान, ओमान, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा संयुक्त रूप से इसकी घोषणा की जाएगी। हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समझौते को अंतिम रूप देने से पहले इसकी शर्तों में बदलाव हो सकता है।

दुश्मन देशों के जहाजों की आवाजाही पर रोक

ईरान ने रविवार को होर्मुज स्ट्रेट के प्रबंधन की योजना में प्रगति का संकेत दिया, लेकिन एक सांसद ने कहा कि दुश्मन देशों के जहाजों की आवाजाही पर रोक रहेगी। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने सामान्य रूपरेखा को मंजूरी दे दी है। इसमें संसद के पीठासीन बोर्ड के एक सदस्य के हवाले से कहा गया है कि जिन देशों ने ईरान को नुकसान पहुंचाया है, वे तब तक आवाजाही नहीं कर सकते जब तक कि वे इसकी भरपाई न कर दें।

होर्मुज का तोड़ निकालने में जुटा रूस! ईरान-पाक होते हुए भारत तक रेल लाइन का प्रस्ताव

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे टकराव से दुनिया भर में उथल-पुथल मची हुई है। दोनों देश होर्मुज जलडमरूमध्य पर पूरा नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे दूसरे देशों के जहाजों का वहां से गुजरना मुश्किल हो रहा है। इसे देखते हुए, रूस अब होर्मुज का कोई विकल्प खोजने की कोशिश कर रहा है। दरअसल, रूस अब हिंद महासागर तक पहुंचने के लिए रेल रूट की संभावना तलाश रहा है।

रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मरात खुसनुलिन ने कहा है कि देश को हिंद महासागर तक रेल कनेक्शन बनाने की संभावना पर विचार करना चाहिए। उनका मानना है कि इससे रणनीतिक रूप से संवेदनशील समुद्री रास्तों पर रूस की निर्भरता कम हो सकती है। रूसी समाचार एजेंसी TASS के मुताबिक, खुसनुलिन ने बोस्फोरस और होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़े जोखिमों का हवाला देते हुए वैकल्पिक ट्रांसपोर्ट रूट की जरूरत बताई। उनके अनुसार, रूस ऐसे किसी भी रूट पर विचार करेगा जो भारत तक पहुंच आसान बनाए।

खुसनुलिन ने एक संभावित रेल कॉरिडोर का खाका पेश किया जो रूस से तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए भारत तक जा सकता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत तक पहुंचने वाला कोई भी विकल्प स्वीकार्य हो सकता है। हालांकि, यह प्रस्ताव अभी शुरुआती चरण में है। इस रेल रूट के निर्माण के बारे में कोई पुष्टि नहीं हुई है, और न ही यात्री सेवाओं, टिकट की कीमतों या लॉन्च की तारीख के बारे में कोई जानकारी दी गई है। इस रूसी प्रस्ताव के पीछे मुख्य वजह अहम समुद्री रास्तों से जुड़ा जोखिम है। होर्मुज जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। सामान्य परिस्थितियों में, दुनिया की लगभग एक-पांचवीं ऊर्जा आपूर्ति इसी रास्ते से होती है। वहीं, बोस्फोरस जलडमरूमध्य काला सागर को मरमारा सागर से जोड़ता है। रूस इस जलमार्ग से बचने के लिए वैकल्पिक रास्तों की जरूरत भी महसूस करता है, क्योंकि इस पर तुर्की का नियंत्रण है। माना जा रहा है कि अगर यह प्रस्ताव असल में रेल कॉरिडोर का रूप ले लेता है, तो यह भारत और रूस के बीच जमीन के रास्ते कनेक्टिविटी का एक नया विकल्प बन सकता है। रूस को हिंद महासागर क्षेत्र में सामान पहुंचाने के लिए समुद्री रास्तों का एक विकल्प मिल जाएगा। भारत के लिए भी, इससे रूस और मध्य एशियाई देशों के साथ कनेक्टिविटी बेहतर हो सकती है। हालांकि, चूंकि यह रूट कई देशों से होकर गुजरेगा, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांजिट, सुरक्षा और सीमा-पार आवाजाही को लेकर बड़े पैमाने पर तालमेल की जरूरत होगी।

व्हाइट हाउस में बड़ा फेरबदल... ट्रंप ने अपने संकटमोचक वकील विल शार्फ को बनाया चीफ काउंसल, 1 सितंबर से संभालेंगे कमान

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रशासन में बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने अपने स्टाफ सेक्रेटरी विल शार्क (Will Scharf) को नया 'व्हाइट हाउस काउंसिल' और 'असिस्टेंट टू द प्रेसिडेंट' यानी राष्ट्रपति के सहायक के रूप में नियुक्त करने का ऐलान किया है। शार्क 1 सितंबर से डेविड वॉरिंगटन की जगह यह जिम्मेदारी संभालेंगे। डेविड प्रशासन छोड़कर अब प्राइवेट सेक्टर में जाने वाले हैं।

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट के जरिए विल शार्क की नियुक्ति की जानकारी शेयर की। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्टाफ सेक्रेटरी विल शार्क 1 सितंबर से नए व्हाइट हाउस काउंसिल और असिस्टेंट टू द प्रेसिडेंट का पदभार संभालेंगे। ट्रंप ने बताया कि शार्फ डेविड वॉरिंगटन की जगह लेंगे,

जिन्होंने व्हाइट हाउस काउंसिल के रूप में और उससे पहले उनके राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान बेहद उत्कृष्ट काम किया है। उन्होंने बताया कि डेविड अब प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं। ट्रंप ने विल शार्फ की तारीफ करते हुए उन्हें मजबूत, सख्त और बुद्धिमानबताया। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा 'विल शार्क दृढ़, बलवान और बुद्धिमान हैं! वे हमारे देश से प्रेम करते हैं और कानून का सम्मान करते हैं'। ट्रंप ने कहा कि विल शार्फ व्हाइट हाउस के वकील के रूप में शानदार काम करेंगे।

व्हाइट हाउस के 'स्टाफ सेक्रेटरी' के रूप में कार्यरत

वर्तमान में विल शार्क व्हाइट हाउस के 'स्टाफ सेक्रेटरी' के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वो नेशनल कैपिटल प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं । वो संघीय अभियोजक के रूप में भी काम कर चुके हैं। उन्होंने कई कानूनी मामलों में ट्रंप का प्रतिनिधित्व किया है। इनमें अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से जुड़े मामले भी शामिल हैं।

हार्वर्ड लॉ स्कूल से कानून की डिग्री हासिल की

विल शार्क ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से स्नातक और हार्वर्ड लॉ स्कूल से कानून की डिग्री हासिल की है। उन्होंने निजी प्रैक्टिस में एक वकील के रूप में कार्य किया है। उन्होंने दो फेडरल अपील्स कोर्ट जजों के पास क्लर्क के तौर पर काम किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि बाइडन प्रशासन के दौरान उनके खिलाफ चले मामलों में विल शार्क ने सुप्रीम कोर्ट समेत कई अदालतों में उनका प्रतिनिधित्व किया था। ट्रंप ने विश्वास जताया कि शार्क कानून का सम्मान करते हुए व्हाइट हाउस काउंसिल के रूप में बेहतरीन काम करेंगे।

ट्रंप के बॉलरूम प्रोजेक्ट से भी जुड़ा नाम

विल शार्फ का नाम ट्रंप के व्हाइट हाउस बॉलरूम प्रोजेक्ट से भी जुड़ा है। जुलाई 2025 में ट्रंप ने उन्हें नेशनल कैपिटल प्लानिंग कमीशन का अध्यक्ष बनाया था। इसी संस्था ने व्हाइट हाउस में प्रस्तावित करीब 400 मिलियन डॉलर के बॉलरूम प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। अप्रैल में इस परियोजना को अंतिम मंजूरी मिली थी। हालांकि शुक्रवार को एक संघीय अपीली अदालत ने निर्माण रोकने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि परियोजना के लिए कांग्रेस की मंजूरी नहीं ली गई थी। ट्रंप ने इस फैसले को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। व्हाइट हाउस में यह बदलाव ऐसे समय हुआ है जब अमेरिका में मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं।

शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के घर से आएगा? इथेनॉल विरोध पर भड़के भाजपा सांसद! कांग्रेस बोली- जिनके बाप...

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद जनार्दन मिश्रा ने इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी को लेकर केंद्र सरकार का बचाव करते हुए विपक्षी पार्टियों से पूछा कि क्या शुद्ध पेट्रोल उनके पिता के घर से आएगा, जिससे भारी विवाद खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश के रीवा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सांसद मिश्रा ने रविवार को रीवा से भोपाल और कोलकाता के लिए नई उड़ान सेवाओं के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। केंद्र का बचाव करते हुए और अमेरिका (US) और ईरान के बीच संघर्ष के कारण चल रही वैश्विक उथल-पुथल का हवाला देते हुए, मिश्रा ने बताया कि भारत केवल 20 प्रतिशत कच्चा तेल पैदा करता है, जबकि बाकी 80 प्रतिशत आयात किया जाता है। उन्होंने दावा किया कि तेल की आपूर्ति के लिए जहाज लगभग 18,000 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करते हैं। मिश्रा ने कहा एक अभियान चल रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि इथेनॉल काम नहीं करेगा, शुद्ध पेट्रोल ही काम करेगा। क्या शुद्ध पेट्रोल आपके पिता के घर से आएगा? अगर देश में शुद्ध पेट्रोल नहीं है, तो यह कहां से आएगा? बीजेपी के लोकसभा सांसद ने कहा कि भारत में गाड़ियां इथेनॉल ब्लेंडिंग पर चल सकती हैं। उन्होंने दावा किया कि ब्राज़ील में गाड़ियां पूरी तरह से 100% इथेनॉल पर चलती हैं और उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। उन्होंने कहा कि अगर इथेनॉल नहीं बनेगा, तो पेट्रोल और डीज़ल कहाँ से आएगा? ब्राज़ील दुनिया में सबसे ज़्यादा इथेनॉल बनाता है, इसीलिए वहाँ गाड़ियाँ 100% इथेनॉल पर चलती हैं।

भारतीय सीमा में घुसकर दीपांकर को उठा ले गए बांग्लादेशी, रिहाई की कोशिशों में जुटी बीएसएफ

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत और बांग्लादेश के बीच एक बार फिर तनाव की स्थिति बनती दिख रही है। दोनों देशों की सीमा से सटे पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से एक भारतीय नागरिक दीपांकर गोप को बांग्लादेशी लोगों ने अगवा कर लिया। अगवा किए जाने की घटना के बाद दोनों ओर तनाव बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि अगवा किया गया भारतीय एक चाय किसान है और उसे बांग्लादेश पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस अब उसके खिलाफ केस दर्ज करने की योजना बना रही है।

दीपांकर गोप की सुरक्षित रिहाई की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। भारतीय सीमा में घुसकर दीपांकर को उठा ले जाने की घटना के बाद सीमा

सुरक्षा बल (BSF) बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) के साथ लगातार संपर्क में हैं और उसकी सुरक्षित रिहाई के लिए बातचीत कर रही है।

इससे पहले बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) ने 35 साल के किसान दीपांकर को पंचगढ़ पुलिस स्टेशन को सौंप दिया। पंचगढ़ पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर (जांच) आशीष कुमार शील ने बांग्लादेशी अखबार 'द डेली स्टार' को बताया, "उस पर केस दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। केस दर्ज होने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट के आदेश के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।"

यह घटना तब हुई जब स्थानीय लोगों ने दीपांकर गोप को बिराजोत बॉर्डर (Birajot border) के पास बॉर्डर पिलर 742/12 के पास गन्ने के खेत में हिरासत में लिया। उनका दावा था कि वह पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में घुस आया था। हालांकि, भारतीय रिपोर्टों में यह दावा किया गया था कि दीपांकर बांग्लादेश में नहीं घुसा था, बल्कि बदला लेने के मकसद से बांग्लादेश के करीब 15 लोगों ने उसे अगवा कर लिया था।

चाय के बागान से किसान को जबरन उठा ले गए

खबरों के मुताबिक, अपहरण की यह घटना शनिवार सुबह हुई, जब वह पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के कुकुरजन इलाके में अपने चाय के खेत में अकेले ही कीटनाशक दवा का छिड़काव कर रहा था। यह इलाका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) की चौलहाटी चौकी के अधिकार क्षेत्र में आता है। दावा किया जा रहा है कि कम से कम 15 बांग्लादेशी लोग अचानक से भारतीय सीमा में घुस आए और जो उसके खेत से महज 140 मीटर दूर थी और उसे जबरन अपने साथ उठाकर ले गए। अपहरण की घटना के बाद, सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवान मौके पर पहुंचे और गोप को छुड़ाने की कोशिशें शुरू कर दीं।

BGB अधिकारियों के साथ BSF की फ्लैग मीटिंग

उन्होंने BGB अधिकारियों के साथ फ्लैग मीटिंग भी की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इस बीच, गोप का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उसे उठाकर ले जाने वाले स्थानीय बांग्लादेशी लोग कह रहे हैं कि उसे तभी छोड़ा जाएगा जब तमीज उद्दीन को रिहा किया जाएगा। तमीज बांग्लादेश का एक नागरिक है, जिसे BSF ने इस हफ्ते की शुरुआत में चौलहाटी बॉर्डर पर कंटीले तार काटकर बांग्लादेश से भारत में घुसने की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। हालांकि, बांग्लादेश के स्थानीय लोगों का दावा है कि तमीज बुजुर्ग नागरिक हैं और हिरासत में लिए जाने के समय सिर्फ अपनी खोई हुई गाय को ढूंढ रहे थे। दीपांकर को उठाए जाने की घटना ने बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों में चिंता पैदा कर दी है, और BSF उसकी सुरक्षित रिहाई के लिए BGB के लगातार संपर्क में है। मामले के दोनों पक्षों की बारीकियों की भी जांच की जा रही है।

'यह मुश्किल है...', भूमि पेडनेकर असम बाढ़ प्रभावितों के लिए आगे आईं, पोस्ट साझा कर वॉलंटियर्स को सराहा

असम में आई बाढ़ से कई लोग प्रभावित हैं। आम लोगों की मदद के लिए भूमि पेडनेकर आगे आई हैं, असम के शिवसागर में उन्होंने राहत सामग्री बांटी। साथ ही वॉलंटियर्स को सराहते हुए एक पोस्ट भी साझा की।

भूमि पेडनेकर असम के शिवसागर जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंची थीं। उन्होंने वहां पहुंचकर राहत सामग्री लोगों को बांटी। इसके अलावा सोशल मीडिया के जरिए इस काम में लगे वॉलंटियर्स की तारीफ की। साथ ही फैंस से असम बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए दान देने की अपील की।

अपने इंस्टाग्राम पेज पर बाढ़ प्रभावितों की मदद करते हुए एक वीडियो भूमि पेडनेकर ने पोस्ट किया है। इसके अलावा एक इंस्टाग्राम स्टोरी भी लगाई है, जिसमें उनकी गाड़ी बाढ़ वाले पानी में चल रही है। इस पोस्ट के साथ वह लिखती हैं, 'यह मुश्किल है। आपको इसे अनुभव करना होगा, जिससे आप समझ सकें कि इसका असर कितना गहरा है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन और सभी वॉलंटियर्स को सलाम करती हूं क्योंकि वह बाढ़ से प्रभावित होने के बावजूद 24 घंटे काम कर रहे हैं।'

भूमि पेडनेकर के साथ इस मुहिम में भारत डिजास्टर रिलीफ फाउंडेशन के वॉलंटियर भी शामिल थे। यह संस्था जुलाई के आखिर से शिवसागर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य कर रही है। यह संस्था प्रभावित समुदायों को भोजन, जरूरी सामान और दूसरी जरूरी सहायता पहुंचा रही है। साथ ही रिकवरी और पुनर्वास के काम में भी मदद कर रही है।

करियर फ्रंट पर क्या कर रही हैं भूमि पेडनेकर?

भूमि पेडनेकर के करियर फ्रंट की बात करें तो वह फिल्म 'द प्राइड ऑफ भारतः छत्रपति शिवाजी महाराज' का हिस्सा बनी हैं। इस फिल्म में ऋषभ, शिवाजी महाराज के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म में भूमि पेडनेकर वॉरियर क्वीन बेलवाडी मल्लम्मा का किरदार निभाएंगी।

सीजेपी प्रोटेस्ट पर सिद्धार्थ और दीया मिर्जा ने की छात्रों की तारीफ, कहा- 'बोलने के लिए किसी की इजाजत नहीं चाहिए'

दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अलग-अलग हिस्सों में जून-जुलाई के दौरान हुए CJP प्रोटेस्ट पर कई एक्टर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी। दीया मिर्जा ने भी छात्रों के समर्थन में अपनी आवाज उठाई। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा कि वह छात्रों के अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और एजुकेशन सिस्टम में सुधार की मांग का समर्थन करती हैं।

वहीं, उनकी 'ऑपरेशन सफेद सागर' के को-स्टार सिद्धार्थ ने 'वी आर युवा' से बात करते हुए छात्रों की परेशानियों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि एग्जाम पेपर लीक जैसी घटनाओं से किसी भी परिवार को अपने बच्चे को नहीं खोना चाहिए। साथ ही उन्होंने एक्टर्स और पब्लिक फिगर्स के बोलने के अधिकार का बचाव करते हुए कहा कि लोगों को उनकी पर्सनल राय के लिए उन्हें ट्रोल नहीं करना चाहिए।

अब न्यूज 18 से बातचीत में सिद्धार्थ ने देश के युवाओं की जमकर तारीफ की। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की पंक्तियां दोहराते हुए कहा, 'अभी भी जिसका खून ना खौला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आए, वो बेकार जवानी है।' उन्होंने आगे कहा, 'ये हर दौर के युवाओं पर लागू होता है। उन्हें बस खुद को एक्सप्रेस करना चाहिए। उन्हें हमारी परमिशन या सलाह की जरूरत नहीं है।'

मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं

सिद्धार्थ अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। वह अक्सर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें आलोचना का सामना करना पड़े। इस पर उन्होंने कहा, 'जब मैंने बोलना शुरू किया था, तब भी मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं थी और आगे भी नहीं होगी। युवा हमेशा युवा रहेंगे। समय के साथ उनकी जगह नई पीढ़ी लेती रहेगी।'

दीया मिर्जा ने की युवाओं की तारीफ

वहीं, दीया मिर्जा ने भी युवाओं की तारीफ करते हुए कहा, 'हमें उनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है।' उन्होंने कहा कि अपनी बात रखने से कोई नुकसान नहीं होता, 'यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसे नुकसान मानते हैं। अगर आप सच्चाई और प्यार के साथ अपनी बात रखते हैं, तो खोने के लिए कुछ भी नहीं होता।'

टॉक्सिक का ट्रेलर रिलीज, यश के स्टाइल और स्वैग के आगे विलेन ढेर, गर्ल गैंग ने भी मचाया तहलका

कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से पैन इंडिया स्टार बने केजीएफ फेम एक्टर यश पूरे चार साल बाद फिल्म टॉक्सिक से धमाका करने आ रहे हैं। टॉक्सिक साल 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है और आज टॉक्सिक का ट्रेलर रिलीज हो गया है। यश के फैंस को टॉक्सिक के ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार था, जो आज आखिरकार खत्म हो चुका है। टॉक्सिक अपने पहले दिन से ही चर्चा में है और जब फिल्म का पहला टीजर रिलीज हुआ था, तब से विवादों में भी छाई रही, लेकिन अब फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद फैंस के लिए इसका इंतजार करना और भी मुश्किल हो सकता है। टॉक्सि की टीम ने आज बैंगलुरु में लॉन्चिंग इवेंट पर फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है।

टॉक्सिक का ट्रेलर अपने पहले ही सेकंड से दर्शकों के बांधने का काम करता है। यश की अपीरियंस और उनका स्टाइल फैंस को केजीएफ से बिल्कुल अलग खड़ा करता है। एक्शन और स्टंट से भरे टॉक्सिक के ट्रेलर में यश फिल्म की हसीनाओं संग रोमांटिक नजर आ रहे हैं। ट्रेलर में नयनतारा, कियारा आडवाणी, रुक्मिणी वसंत, तारा सुतारिया और हुमा कुरैशी अपने अलग-अलग अंदाज में दिख रहे हैं। दूसरी तरफ केजीएफ के रॉकी भाई यश अपने स्टाइल और स्वैग में हर सीन में जान फूंकते नजर आ रहे हैं। ट्रेलर देखने के बाद दर्शकों के लिए फिल्म का इंतजार करना मुश्किल होने वाला है। बता दें, फिल्म 26 अगस्त को रिलीज होने जा रही है।

यश स्टारर फिल्म टॉक्सिक का निर्देशन गीतू मोहनदास ने किया है। केवीएन प्रोडक्शंस और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन मिलकर फिल्म का निर्माण किया है। वहीं, फिल्म की खास बात यह भी है कि इसमें पांच खूबसूरत हसीनाएं नयनतारा, कियारा आडवाणी, रुक्मिनी वसंत, तारा सुतारिया और हुमा कुरैशी हैं, जो रोमांस के साथ-साथ एक्शन भी करती नजर आएंगी। फिल्म के पोस्टर और टीजर पहले ही धमाका मचा चुके हैं। वहीं, फिल्म से रिलीज हुए गानों में यश एक-एक एक्ट्रेस संग रोमांस करते नजर आ रहे हैं। अब देखना है कि चार साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर लौट रहे यश क्या दर्शकों की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं या नहीं।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित।
शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website: aryavartkranti.com
*सम्पादक: प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com